www.ghoonghatkibagawat www.ghoonghatkibagawat ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

# घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित | हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 02 | गोरखपुर, 07 जुलाई 2024 रविवार | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 2

**यह वह संसद है जिसके शब्दों का कोई मोल ही नहीं रह गया है। शेरो-शायरी भी हो रही है, कहावतें भी दोहराई जा रही हैं, प्रधानमंत्री बड़े-बड़े विचारकों -दार्शनिकों के उद्धरण भी ला-लाकर पढ़ते हैं, लेकिन सब-के-सब इतने प्रभावहीन क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि उनके पीछे विश्वसनीयता का बल नहीं है। आस्थाहीन प्रवचन आत्माहीन कंकाल की तरह होता है। यह लंगड़ी व पतनशील गठबंधनों के सांसदों से बनी संसद है। विपक्ष के नेता व संपूर्ण विपक्ष को लगातार यह दबाव बनाए रखना चाहिए कि यह संसद सुधरे और बदले!**

## संसद को सुधारने और बदलने की जिम्मेदारी विपक्ष की

राहुल गांधी ने जब यह कहा कि उनका माइक बंद क्यों किया गया, तो अध्यक्ष का जवाब आया कि मैंने पहले भी यह व्यवस्था दी है कि मेरे पास माइक का कोई बटन नहीं है। क्या अध्यक्ष की जानकारी व अनुमति के बगैर ही कोई, कहीं से बैठकर लोकसभा की कार्रवाई में दखल दे रहा है? अगर ऐसा है तो अध्यक्ष चाहिए ही क्यों? जो अनदेखा-अनजाना आदमी बटन बंद कर सकता है, वही लोकसभा चला भी सकता है। 'इंडिया गठबंधन' को तब तक न लोकसभा जाना चाहिए, न राज्यसभा जब तक कि यह बता न दिया जाए कि माइक बंद किसने किया था, किसकी अनुमति या निर्देश से किया दि था? यह तो विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है।

परंपरा की बात है तो यह समझना जरूरी है कि विपक्ष के नेता की भी परंपराएं हैं। अध्यक्ष को न वे परंपराएं पता हैं, न विपक्ष के नेता का मतलब मालूम है। जिन सांसदों का जन्म ही 10 साल पहले हुआ है, उनकी यह त्रासदी स्वाभाविक है। उनकी तो आंखें जब से खुली हैं तब से उन्होंने यही देखा-जाना है कि लोकसभा का मतलब एक ही आदमी होता है। जैसे यह परंपरा है कि अध्यक्ष जब खड़ा हो व जाए तो सभी सांसदों को बैठ जानी चाहिए; प्रधानमंत्री जब बोल रहा हो तब सांसदों को शाति से उसे सुनना चाहिए; वैसी ही परंपरा यह भी है कि विपक्ष का नेता जब बोल रहा हो तब उसे अध्यक्ष द्वारा बार-बार टोकना, बार-बार समय का भान कराना, क्या बोलें, क्या न बोलें आदि का निर्देश देना गलत है, अशिष्टता है, लोकतांत्रिक है परंपरा का उल्लंघन है। आखिर परंपराएं बनती कैसे हैं और उन्हें ताकत कहां से मिलती है? परंपराएं कानूनी प्रावधानों से भी अधिक मान्य क्यों होती हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई भी उन्हें तोड़ता नहीं है। संविधान प्रदत्त शक्तिवान भी उनका शालीनता से पालन कर, उसे और अधिक व मजबूत व काम्य बनाते हैं। राष्ट्र्गान चल रहा हो तब राष्ट्रपति के सामने से धडधड़ाते हुए निकलकर अपनी कुर्सी पकड़ने वाला लोकसभा अध्यक्ष हो कि राष्ट्रपति प्रवेश करें तब भी अपनी कस्सी पर बैठा रहने वाला प्रधानमंत्री, ये सब हरकतें परंपराओं को ठेस पहुंचाती हैं। पिछले महीने गठित देश की ताजा-तरीन 18वीं लोकसभा क्या सचमुच हमारे लोकतंत्र की सरक्षक हो पाएगी ? उसके उद्घाटन-सत्र में ही जिस तरह के कारनामें हुए, क्या वे लोकतंत्र में भरोसा करने वाले नार्गरिकों की अपेक्षा ओं पर खरें तरते दिखते हैं? यह सवाल नई लोकसभा के गठन के साथ ही शुरू हो गए है। हमारी नई लोकसभा अभी बनी ही है, लेकिन चल नहीं पा रही। चल पाएगी, इसमें शक है। चलकर भी क्या कर पाएगी, कह नहीं सकते। कहावत बहुत पुरानी है जो हर अनुभव के साथ नई होती रहती है कि ४पूत के पांव पालने में ही दीख जाते हैं। जो पांव दीख रहा है, वह शुभ नहीं है। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो कवि विजयदेव नारायण साही ने इस कहावत में एक दूसरीं मा्मिक पक्ति जड़ दी थी पूत के पांव पालने में मत देखो/ वह पिता के फटे जूते पहतने या है। इस लोकसभा के बारे में यही पक्ति बार-बर मन में गुंज रही है। जिस पार्टी ने, जिन पार्टियों के साथ जोड़ विठाकर सरकार बनाई है, उन सबको मालूम है कि यह वक्ती व्यवस्था है। कौन, पहले, किसे और कब लंगड़ी मारता है, इसी पर इस लोकसभा का भविष्य टिका है, और यह तो सारे संविधानज्ञ जानते हैं कि लोकसभा के भविष्य पर ही सांसद नाम के निरीह प्रणियों का भविष्य टिका होता है। निरीह इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कम-से-कम 10 सालों से हमारे सांसदों का एक ही काम रहा है, जिसे वे बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। सरकार की दी हुई मेज थपथपाना या भगवान की दी हुई हथेलियों से तालियां बजाना। विपक्ष भी ऐसा ही करता है। फर्क है तो बस इतना कि उसके

पास कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। इस बार उसके पास एक 'छाया प्रधानमंत्री' जरूर है जिसकी छाया कब तक, कहां तक रहती है, देखना बाकी है। हम दुआ करते हैं कि अंग्रेजी के 'शैड़ो प्राइम- मिनिस्टर' का मक्खीमार अनुवाद भले उसे ४छया प्रधानमंत्री' कहे, नेता प्रतिपक्ष कभी इस प्रधानमंत्री की छाया न बनें। न उनकी छाया

में रहें, न उनको छ्या दें। ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनाने के पीछे प्रधानमंत्री का एक ही मकसद रहा, विपक्ष को आखिरी हद तक अपमानित करना। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में माना जाता है कि वह विद्वता, कार्यकुशलता, व्यवहार-कुशलता, वाकपटुता तथा सदन में गरिमामय माहौल बनाये रखने की महारत हासिल होगी। लेकिन ऐसा सदन में दिख नहीं रहा है। पिछले पांच भी ओम विरला का लोगों ने देखा ही है कि लोकसभा में विपक्ष के साथ क्या-क्या किया?

पता नहीं इस विपक्ष ने उनका इतना स्वागत व गुणगान क्यों किया! ओम बिरला ने पिछली संसद में जिस तरह विपक्ष को तिरस्कृत व अपमानित किया था, उसे ही दोहराने के लिए इस बार भी उन्हें ही प्रधानमंत्री ने आगे किया है ताकि विपक्ष के समझ सके कि कुछ भी बदला नहीं है। नई लोकसभा के पहले दिन ही में अपने पुराने अवतार में दिखाई दिए। विश्व सभ्यता से उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को अपमानित किया शशि थरूर के जय संविधान खाने से तेल मिले विपक्ष के सांसदों को कब उठना कब बैठना सीखने की फब्ती कसी वह सब यह समझने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें क्या करने का निर्देश हुआ है।

अंधभक्त अपनी फिक्र आप करें, लेकिन हम-आप तो सोचें कि ऐसा क्यों है कि सत्तापक्ष के सारे शब्द इतने खोखले शिक्षामंत्री ठीक ही तो कह रहे थे कि 'नीट के बारे में हम विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। वे कह तो रहे थे, लेकिन उनके हाव- भाव व तेवर यह कहते सूनाई दे रहे थे कि कर लो जो करना हो, हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था कि इसी मंत्री ने, इसी 'नीट' के बारे में लगातार यही कहा था कि न कोई लीक हुआ है, न कोई घोटाला हुआ है, सब विपक्ष का किया-धरा है।

राहल गांधी चाहें-न- चाहें, वे कसौटी पर हैं। आज नेता-प्रतिपक्ष शोभा का पद नहीं है। आज यह पद विकल्प खड़ा करने की चुनौती का पद है। विपक्ष को वक्त की सीधी चुनौती यह है कि क्या पंडित जवाहरलाल के दौर वाली संसद वापस लाने की कुवत उसमें है?

नेहरू वाली संसद इसलिए कह रहा हं कि हमने वहीं से अपना सफर शुरू किया था और लगातार फिसलते हुए यहां आ पहुंचे हैं। तो कैसे कहूं कि उस दौर से भी बेहतर संसद बनानी चाहिए! पहले वहां तक तो पहुंचो, जहां से गिरे थे, फिर उससे ऊपर उठने की बात करेंगे।

राहुल गांधी व 'इंडिया गठवंधन' ने संविधान की किताब दिखा- दिखाकर प्रधानमंत्री को जिस तरह चुनाव में कमजोर किया, उसकी काट उन्होंने यह निकाली कि लोकसभा अध्यक्ष को मोहरा बना कर आपतकाल की निदा का प्रस्ताव पारित करवाया। यह उस विज्ञापन की तरह था कि 'उसकी कमीज मुझसे सफेद कैसे ?' लेकिन कांग्रेस को इससे बौखलाने की क्या जरूरत थी? कोई 50 साल पहले हुई चूक, जिसे इंदिरा गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष ने कई बार सार्वजनिक रूप स्वीकार किया है, उसे लेकर कांग्रेस अब क्यों विलबिलाती है? वह इतिहास की बात हो गई। यह भी याद रखना चाहिए

कि जनता पार्टी की अल्पजीवी सरकार ने 1977 में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था खुड़ी भी कर दी है कि किसी सरकार के लिए आपातकाल लगाना असंभव-सा है। यह वह संसद है जिसके शब्दों का कोई मोल ही नहीं रह गया है। शेरो-शायरी भी हो रही है, कहावतें भी दोहराई जा रही हैं, प्रधानमंत्री बड़े-बड़े विचारकों -दार्शनिकों के उद्धरण भी ला-लाकर पढ़ते हैं, लेकिन सब-के-सब इतने प्रभावहीन क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि उनके पीछे विश्वसनीयता का बल नहीं है। आस्थाहीन प्रवचन आत्माहीन कंकाल की तरह होता है। यह लंगड़ी व पतनशील गठबंधनों के सांसदों से बनी संसद है। विपक्ष के नेता व संपूर्ण विपक्ष को लगातार यह दबाव बनाए रखना चाहिए कि यह संसद सुधरे और बदले!

## अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, राष्ट्रपति ने पत्नी को सौंपा गौरव

**देवरिया(जीकेबी)।** सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 को तड़के साढ़े तीन बजे भारतीय सेना के कई टेंट में आग लग गई। हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर देवरिया निवासी कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए। अंशुमान सिंह की 5 महीने पहले 10 फरवरी को शादी हुई थी। कैप्टन अंशुमान 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सादे समारोह में यह सम्मान उनकी शहीद की विधवा सृष्टि सिंह और उनकी मां मंजू सिंह को सौंपा।

सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 को तड़के साढ़े तीन बजे भारतीय सेना के कई टेंट में आग लग गई। हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर देवरिया निवासी कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए। अंशुमान सिंह की 5 महीने पहले 10 फरवरी को शादी हुई थी।

कैप्टन अंशुमान 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। अंशुमान मूल रूप से देवरिया जिले के बरडीहा गांव के रहने वाले थे। 5 महीने पहले लखनऊ के पारा मोहान रोड स्थित जिस घर में कैप्टन अंशुमान सिंह की शादी की शहनाई गूंजी थी, वहां गुरुवार को मातम पसरा था।

अंशुमान सिंह के अद्वितीय साहस को देखते हुए कीर्ति चक्र देने की घोषणा की गई थी। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सादे समारोह में यह सम्मान उनकी शहीद की विधवा सृष्टि सिंह और उनकी मां मंजू सिंह को सौंपा।

### यह है पूरा घटना क्रम

वर्ष 2023 तारीख 20 जुलाई दिन बुधवार सुबह सेना की मेडिकल कोर और कमांड अस्पताल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अंशुमान सिंह के लखनऊ स्थित घर पहुंचे। उन्होंने पिता रवि प्रताप सिंह को कैप्टन

अंशुमान सिंह के शहीद होने की खबर दी। शहादत की खबर मिलते ही उनके परिचितों और रिश्तेदारों का घर पहुंचना शुरू हो गया। बेहाल मां मंजू सिंह का रो रोकर बुरा हाल हो गया।

अंशुमान सिंह की पत्नी इंजीनियर सृष्टि सिंह पठानकोट की रहने वाली हैं। वह नोएडा में रहकर एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करती हैं। अंशुमान के लखनऊ वाले घर में उनके पिता रवि प्रताप सिंह, मां मंजू सिंह, बहन तान्या सिंह और भाई घनश्याम सिंह रहते हैं।

देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के बरडीहा दलपत में उनके दादा और चाचा रहते हैं। पढ़ाई के बाद अंशुमान का चयन आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में हो गया। वहां से टइइर करने के बाद कैप्टन अंशुमान सिंह सेना की मेडिकल कोर में शामिल हुए। पत्नी स्मृति पेशे से इंजीनियर हैं और उनके माता-पिता स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। आगरा मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के बाद वहीं अंशुमान की तैनाती हो गई थी।

पिछले दिनों कश्मीर के पुंछ सेक्टर में तैनात एक बटालियन के वह मेडिकल आफिसर बने। वहां से 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। उनके पिता रवि प्रताप सिंह सेना में खउड थे। कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह के अलावा भाई घनश्याम सिंह और बहन तान्या सिंह हैं। दोनों ही नोएडा में डॉक्टर हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की थी। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद अंशुमान सिंह के नाम पर करने की भी घोषणा की थी।

# राष्ट्रपति मुर्मू ने 36 वीर जांबाजों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित

**नई दिल्ली।** दम्य साहस व वीरता का परिचय देने वाले सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों व पुलिस कर्मियों को शुक्रवार शाम कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 05 जुलाई, 2024 को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह (चरण-1) के दौरान 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के पुलिसकर्मियों को विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रदान किये गए।

सीआरपीएफ 210 कोबरा के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू रभा व कांस्टेबल शंभू रॉय को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना की ग्रेनेडियर 55 बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही पवन कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वह आर्मी मेडिकल कॉर्पस 26 बटालियन पंजाब रेजीमेंट में थे। हवलदार अब्दुल माजिद को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार अब्दुल भारतीय सेना की, 9 बटालियन पैराशूट रेजीमेंट, स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। इन सभी बहादुर सपूतों के परिजनों ने यह सम्मान प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सफीउल्लाह कादरी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। भारतीय सेना की आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के मेजर विकास व मेजर मुस्तफा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सेना के राइफलमैन कुलभूषण, जो जम्मू कश्मीर राइफल्स 52 बटालियन, राष्ट्रीय राइफल में थे, उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राजपूताना राइफल्स, 5 बटालियन के हवलदार विवेक सिंह तोमर, 18 असम राइफल्स के राइफलमैन आलोक राव व कैप्टन एमवी प्रांजल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन प्रांजल कॉर्पस ऑफ सिग्नल 63 बटालियन राष्ट्रीय राइफल में थे। परिजनों को आर्मी के मेजर दिग्विजय सिंह रावत, मेजर दीपेंद्र विक्रम बस्नेत, नायब सूबेदार पवन कुमार यादव कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए हैं।

शौर्य चक्र से सम्मानित होने वालों में कांस्टेबल मुकेश कुमार, जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अमित रैना, फिरोज अहमद डार, कांस्टेबल वरुण सिंह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहनलाल, उफ्ळ्त्रके असिस्टेंट कमांडेंट बिभोर कुमार सिंह, आर्मी के मेजर राजेंद्र प्रसाद, मेजर रविंद्र सिंह रावत, नायक भीम सिंह, मेजर सचिन नेगी, मेजर मानेओ फ्रांसिस, एयर फोर्स के विंग कमांडर शैलेश सिंह, नेवी के लेफ्टिनेंट विमल रंजन, आर्मी के हवलदार संजय कुमार, एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट ऋषिकेश जयन, आर्मी के कैप्टन अक्षत उपाध्याय, नायब सूबेदार संजय कुमार, मेजर अमनदीप जाखड़ और सिविलियन आर्मी के पुरुषोत्तम कुमार शामिल हैं। इस दौरान इन वीरों की शौर्य गाथा भी सुनाई गई।

▸ वायुसेना के इतिहास का नया अध्याय

# हथियार प्रणाली स्कूल का हुआ उद्घाटन

**नई दिल्ली।** हैदराबाद के एयर फोर्स स्टेशन बेगमपेट में वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल (डब्ल्यूएसएस) का उद्घाटन किया। इसी के साथ भारतीय वायु सेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। वायु सेना को भविष्य में आधुनिक बल के रूप में बदलने के उद्देश्य से यह नया प्रशिक्षण संस्थान सशस्त्र बलों के लिए भी बड़ी छलांग साबित होगा।

वायु सेना प्रमुख ने 08 अक्टूबर, 2022 को वायु सेना दिवस परेड समारोह के दौरान इसके निर्माण की घोषणा की थी।

वायु सेना के मुताबिक यह हथियार प्रणाली स्कूल भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नवगठित शाखा के अधिकारियों को तैयार करेगा। डब्ल्यूएस शाखा के फ्लाइट कैडेट इस संस्थान में अपने दूसरे सेमेस्टर का प्रशिक्षण लेंगे।

नई शाखा में चार स्ट्रीम होगी, जिनमे सुखोई-30 एमकेआई और सी-130जे जैसे हवाई प्लेटफार्मों में हथियारों और प्रणालियों को संचालित करने के लिए फ्लाइंग स्ट्रीम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को संचालित करने के लिए रिमोट स्ट्रीम होगी। इसके अलावा सतह से हवा और सतह से सतह पर हथियार प्रणालियों के लिए मिशन कमांडर और ऑपरेटर और अंतरिक्ष आधारित खुफिया और इमेजरी को संभालने के लिए अलग इंटेलिजेस स्ट्रीम होगी।

इस मौके पर बातचीत के दौरान वायु सेना प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वायु सेना की इस नई शाखा के साथ जमीन आधारित और विशेषज्ञ हथियार प्रणालियों के संचालक एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, जिससे भारतीय वायु सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने प्रशिक्षको को प्रोत्साहित किया कि वे इस नवगठित शाखा के अग्रणी है, इसलिए उनकी परिकल्पित प्रशिक्षण व्यवस्था की पूरी इमारत मजबूती से खड़ी होगी और निर्णायक वायु शक्ति प्रदान करेगी।

स्कूल के संस्थापक सदस्यों की प्रशंसा करते हुए वायु सेना प्रमुख ने सभी कर्मियों से देश में हथियार प्रणालियों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल को एक नोडल केंद्र के रूप में स्थापित करने का आग्रह किया। वायु सेना प्रमुख का स्वागत वेपन सिस्टम स्कूल के कमांडेट एयर वाइस मार्शल प्रेमकुमार कृष्णस्वामी ने किया। उद्घाटन समारोह में एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, प्रशिक्षण कमान और भारतीय वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें एयर फोर्स अकादमी के कमांडेट, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर के कमांडेंट, एयर फोर्स स्टेशन हकीमपेट के एयर ऑफिसर कमांडिंग और एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट के स्टेशन कमांडर शामिल थे।

## ‘जैन पुराण भाग-तीन आचार्य चरितत्र’ नामक पुस्तक का हुआ विमोचन

# लिखित शब्द भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक: थावरचंद गहलोत

**बेंगलुरू।** कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को जैन दर्शन के अहिंसा के महत्व पर जोर देते हुए युवा पीढ़ी से धर्म और संस्कृति को अपनाने और इसको संरक्षित करने की अपील की। वे यहां अखिल भारतीय जैन मंच द्वारा आयोजित एक समारोह में ‘जैन पुराण भाग-3 आचार्य चरित्र’ नामक पुस्तक का विमोचन करने के बाद बोल रहे थे। गहलोत ने धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करने में धार्मिक साहित्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समाज को संगठित रखने में धर्म के महत्व और लोगों पर इसके धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने जैन दर्शन में वर्णित अहिंसा के महत्व पर जोर दिया और युवा पीढ़ी से धर्म और संस्कृति को अपनाने और इसे संरक्षित करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक सिद्धांतों, नैतिकता, समाजसेवा और ज्ञानोदय जैये महत्वपूर्ण विषयों पर सविस्तार चर्चा की गई है। धार्मिक सेवाओं में बोले गए प्रेरणादायक अंश वर्तमान समुदाय को प्रेरित करते हैं लेकिन जब वे लिखित रूप में उपस्थित होते हैं तो वे शब्द भविष्य की पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं।

14 साल सत्ता में रहे...हार हुई तो साइकिल से निकले पूर्व पीएम मार्क रूट, देख किसी को भी नहीं हुआ यकीन

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को रेलगाड़ियां चलाने वाले लोको पायलटों से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह ह्यरेलवे के निजीकरणह्ल और भर्तियों की कमी का मुद्दा उठाएंगे।

# डेंगू में जानलेवा साबित हो सकती हैं दर्द निवारक दवाएं

## डेंगू से बचाव के सुझाव

डेंगू की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दें, ताकि प्रभावित क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव किया जा सके। कूलर, बाल्टी, फ्लावर पॉट, फ्रिज, घड़े का पानी नियमित बदलें, जिससे उसमें मच्छर अंडे न दे सकें। घर के पास जहां पानी इकट्ठा होता है वहां मिट्टी के तेल की कुछ बूंदे या फिर मोबिल ऑयल डाल दें, बुखार होने पर पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं, निजी लैब की जांच रिपोर्ट की सूचना दें।

**सिद्धार्थनगर (जीकेबी)।** स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि बिना चिकित्सक के दवाओं का सेवन न करें, जो शरीर के लिए घातक हो सकती हैं। चिकित्सकों का कहना है कि बिना चिकित्सक की सलाह के विशेष रूप से डेंगू के मामले में शरीर दर्द से बचने के लिए दर्द निवारक दवाओं का सेवन न करें। इससे प्लेटलेट्स कम होने और किडनी पर खतरे की संभावना अधिक होती है।

कोरोना संक्रमण फैलने के समय से ही स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि सफाई और सावधानी बरतें। यही उन्हें बीमारियों से बचा सकती है। चिकित्सक डॉ. मुस्तकीम अंसारी ने बताया डेंगू के मरीज को बुखार के साथ शरीर में दर्द की शिकायत रहती है। तेज दर्द के चलते लोग दर्द निवारक दवाओं का सेवन बिना चिकित्सक की सलाह के कर रहे हैं। कहा कि मरीज ऐसा न करें। मलेरिया की दवा भी डेंगू में निष्प्रभावी होती है। ऐसे में मरीज चिकित्सक की सलाह के बाद ही दवाओं का सेवन करें।

कई प्रकार की बुखार और दर्द की मिश्रित दवा का सेवन भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। जांच की रिपोर्ट आने तक पैरासिटामोल का सेवन किया जा सकता है।

# फिर सक्रिय होगा मानसून, हेवी रेन अलर्ट

**जयपुर।** देश में मानसून सक्रिय हो गया है और इसका असर राजस्थान में भी दिखने लगा है। राजस्थान में चार दिन तक मानसून की झमाझम होने के बाद उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगा। पता चला है कि भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। इस बार राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अति भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का नया सिस्टम तैयार हो गया है, जो 48 घंटे के भीतर सक्रिय हो जाएगा और तीन दिन तक तेज बारिश का दौर चलेगा।

## पूर्वानुमान

### अजमेर और जयपुर में होगी अच्छी बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना है। प्रदेश के अजमेर जिले में आज अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी जयपुर में भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। फिलहाल दोनों जिलों में तापमान की बात करें, तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास बना हुआ है।

# चिकित्सक ऑनलाइन देखेंगे सीटी स्कैन रिपोर्ट

**संतकबीरनगर (जीकेबी)।** जिला अस्पताल में सीटी स्कैन रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है। इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों को रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। मरीज नंबर बताएंगे तो चिकित्सक इमरजेंसी में लगे कंप्यूटर पर ऑनलाइन रिपोर्ट देख लेंगे। इससे मरीजों को सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी ऑनलाइन करने की तैयारी है।

जिला अस्पताल में प्रतिदिन करीब 20 मरीजों का सीटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन की फिल्म लेकर मरीज डॉक्टर को दिखाता है उसके बाद ही चिकित्सक दवा लिखते हैं। अगर किसी दिन मरीज फिल्म लाना भूल गया तो चिकित्सक उसे लाने के लिए कहते हैं। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की परेशानी को देखते हुए सीटी स्कैन कर रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दिया है। पहले चरण में इमरजेंसी में अलग से कंप्यूटर लगाया गया है, जिसे सीटी स्कैन सेंटर से जोड़ दिया गया है। मरीज का जो नंबर मिलेगा, वही नंबर कंप्यूटर में डालने पर मरीज का पूरा विवरण व सीटी स्कैन की फिल्म दिखने लगेगी। बृहस्पतिवार को इस्-ाकी शुरूआत की गई। इसके लिए चिकित्सक को सीटी स्कैन के कर्मचारियों ने प्रशिक्षित किया। इसके बाद ओपीडी में भी इसे ऑनलाइन करने की तैयारी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को भी ऑनलाइन किया जाएगा।

**सीटी स्कैन कराने वाले मरीजों की रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है। अभी इमरजेंसी में यह सुविधा दी गई है। चिकित्सक सीटी स्कैन सेंटर की लॉगिन व पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद मरीज को जो नंबर मिला होगा उसे सबमिट करेंगे तो रिपोर्ट सामने आ जाएगी और सिटी स्कैन की फिल्म भी दिखेगी। इससे मरीजों को रिपोर्ट भूल जाने की समस्या से निजात मिलेगी।**

**- डॉ. भवनाथ पांडेय,**
**सीएमएस**

## बोलीं महिलाएं

नए कानून में महिलाओं व बच्चों के सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे आपराधिक मामलों में महिलाओं व बच्चों के इलाज का बिना किसी शुल्क के व्यवस्था की गई है। इससे आपराधिक मामलों की शिकार महिला व बच्चों के परिजनों को दवा व इलाज की व्यवस्था के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

- साधना पांडेय,
निवासी, टीचर कॉलोनी

नए कानून में सबसे अच्छी बात है कि पीड़िता को उनके मोबाइल फोन पर समय-समय पर मैसेज मिलेगा। अपने केस के अपडेट की जानकारी के लिए उन्हें थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। थाना पर पहुंचने के बाद महिलाओं को पुलिसकर्मियों के सवाल-जवाब के सामने अक्सर शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता था। ऑनलाइन साक्ष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

- नेहा अग्रवाल,
स्टेशन पुरवा,

# नहीं कर सकेगी पुलिस... गिरफ्तारी में खेल

▸ सात साल से ज्यादा सजा के मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान करनी होगी वीडियोग्राफी

▸ परिजन व रिश्तेदार के होंगे हस्ताक्षर

**संतकबीरनगर (जीकेबी)।** नए कानून के लागू होने के बाद सात साल से ज्यादा सजा के मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान वीडियोग्राफी करना होगा। साथ ही गिरफ्तारी के दौरान किसी रिश्तेदार या परिजन से हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा। दोनों में से किसी के न मिलने पर इलाके के किसी संभ्रांत व्यक्ति को गिरफ्तारी की गवाही देनी होगी।

नए कानून को लेकर पुलिसकर्मी से लेकर जनता भी उहापोह की स्थिति में है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह ज्यादा सुविधाजनक व पारदर्शी है। अधिकारियों की माने तो अब अपराधियों की गिरफ्तारी ज्यादा पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके लिए वीडियोग्राफी करना होगा। इससे पुलिस किसी को अनावश्यक रूप से ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रख सकेगी।

गिरफ्तारी मेमो में परिजन, रिश्तेदार अथवा क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति का मोबाइल नंबर अंकित होगा। आगे किसी कार्रवाई की सूचना उसी नंबर पर फोन अथवा मैसेज के माध्यम से मिलता रहेगा। नए कानून की बारीकियां बताने के लिए संबंधित विभागों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। पुलिस के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारी जन सामान्य को नए कानून का लाभ बता रहे हैं।

### मोबाइल चोरी और लूट की रिपोर्ट लिखाना आसान

पुलिस अभी तक मोबाइल चोरी व लूट की घटना लिखने में कतराती थी। घटना में पुलिस को चोरी व लूट की धारा लगाना पड़ता था। समय रहते खुलासा न होने पर थाना प्रभारी व विवेचक को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। पुलिस ऐसे मामले में मोबाइल फोन गिरने अथवा गिर जाने की तहरीर लिखवाकर ले लेती थी। मोबाइल छिनैती के मामले में नए कानून में अलग व्यवस्था की गई है। अन्य प्रकार की लूट से अलग धारा होने की वजह से इसे दर्ज करने में पुलिस को दिक्कत नहीं होगी। मोबाइल फोन बरामद होने पर असली मालिक को आसानी से मिल जाएगा।

### एप में फीड होगी डॉक्टरी व पोस्टमार्टम की कार्रवाई

नए कानून के तहत सात साल या अधिक सजा के मामले में पीड़ित के मेडिकल परीक्षण या मृतक की पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है। एक एप बनाया गया है, जिसमें केस के हिसाब से सभी वीडियो व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य फीड किए जाएंगे। साक्ष्य को विवेचक अपने जरूरत के हिसाब से कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए अलग से सीडी अथवा पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधिक साक्ष्यों के अधार पर गंभीर मामलों में भी अधिकतम तीन महीने में चार्जशीट लगाना पड़ेगा।

### बच्चों से अपराध कराया तो लगेगी अलग धारा

कई मामलों में शातिर व पेशेवर अपराधी अपने को बचाने के लिए बच्चों की आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग करते हैं। ऐसा करके वह खुद को कार्रवाई के दायरे से दूर रखते हैं। अब ऐसे मामलों में धारा 95 के तहत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है।

### शादी का झांसा देकर इन्कार करने के मामले में अलग धारा

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने व इन्कार करने पर अभी तक दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज किया जाता था। इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या को देखकर नई धारा 69 लागू किया गया है। इस अपराध में इसी तरह के अपराध दर्ज किए जाएंगे। दुष्कर्म के अन्य मामलों से अलग श्रेणी में रखकर विवेचना की जाएंगी।

### वादी को मिलती रहेगी जानकारी

सीओ यातायात केशवनाथ ने बताया कि विभिन्न मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले लोगों को आगे की कार्रवाई का पता नहीं चल पाता है। नए कानून में उनको भी राहत मिलेगा। उनका मोबाइल नंबर रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा, उस पर बयान दर्ज कराने से लेकर चार्जश्-ाीट व एफआईआर हर कार्रवाई का अपडेट समय-समय पर मिलेगा।

# मुस्लिम बूथों पर जमकर हुआ मतदान, सबने लगाया साइकिल को धक्का

**गोरखपुर (जीकेबी)**। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल बूथों पर लगी कतारों का सबसे अधिक फायदा इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को मिला। गोरखपुर सीट पर अधिक संख्या में वोटरों ने साइकिल को धक्का लगाया। इन बूथों पर 49 से 58 प्रतिशत तक मतदान हुआ, जिसमें कई बूथों पर 80 प्रतिशत से अधिक मत सपा प्रत्याशी को मिले। मतगणना के दूसरे दिन बुधवार को कचहरी में बूथों पर हुए मतदान की चर्चा होती रही, जबकि मोहल्लों में भी यह मतदान चर्चा का विषय बना रहा। अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव एवं शुभेंद्र सत्यदेव के साथ अन्य अधिवक्ता भी चर्चा कर रहे थे कि इस बार मुस्लिम बस्तियों में एकतरफा वोट पड़े हैं। भले ही भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली है, लेकिन बूथों पर मिले भाजपा, सपा और बसपा के वोटों की चर्चा हो रही है। इसी बीच विकास श्रीवास्तव ने कहा कि बसपा प्रत्याशी मुस्लिम था, फिर उन्हें वोटरों ने नकार दिया।

ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल बूथों पर जमकर मतदान हुआ, जबकि शहर में मतदान प्रतिशत कम रहा। यही कारण रहा है कि शहरी क्षेत्र में 47.93 प्रतिशत ही मतदान हुआ, जबकि संसदीय क्षेत्र में 54.69 प्रतिशत मतदान हुआ। इस बार संसदीय क्षेत्र में 2019 के चुनाव की अपेक्षा 5.12 प्रतिशत कम मतदान हुआ।

गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के रसूलपुर के बूथ संख्या 36 पर 58 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 737 और भाजपा प्रत्याशी रवि किशन को 39 एवं बसपा प्रत्याशी जावेद जिमनानी को सात मत मिले, जबकि बूथ संख्या 35 पर सपा प्रत्याशी को 792 और भाजपा प्रत्याशी को 16 एवं बसपा प्रत्याशी को 10 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार तुर्कमानपुर के बूथ संख्या 130 पर 56 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें सपा प्रत्याशी को 643, भाजपा प्रत्याशी को 56 एवं बसपा प्रत्याशी को तीन मत प्राप्त हुए। शहर के जाफरा बाजार में भी मुस्लिम बहुल बूथ पर सपा प्रत्याशी को अधिक मत मिला, जबकि भाजपा प्रत्याशी को भी मत प्राप्त हुए। बूथ संख्या 56 पर सपा प्रत्याशी को 342 मत, भाजपा प्रत्याशी को 219 मत एवं बसपा प्रत्याशी को आठ मत प्राप्त हुआ। तिवारीपुर के बूथ संख्या 113 पर 52 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें सपा प्रत्याशी को 595, भाजपा प्रत्याशी को छह और बसपा प्रत्याशी को एक मत प्राप्त हुआ।

बंधों का निरीक्षण करते मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ

# जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने दिए सख्त निर्देश

**गोरखपुर(जीकेबी)**। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सबको न्याय मिलेगा और सबकी पीड़ा दूर की जाएगी। जनता दर्शन में दूसरे जिलों के भी लोग आए थे। सीएम से मिलकर समस्या बताने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा काफी अधिक रही। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने भूमाफिया और दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया को करारा सबक सिखाया जाएगा। उनके रहते कोई भी किसी कमजोर या गरीब को उजाड़ नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जबरन जमीन कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई करें। सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग, माफिया, अपराधी किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए।

सीएम ने अफसरों से कहा कि वे हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि इलाज के लिए उन्हें परेशान न होना पड़े। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दो टूक हिदायत देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में हीलाहवाली अक्षम्य होगी। हर व्यक्ति की समस्या का पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से न्यायोचित समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

# अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया प्रो. शिवाजी सिंह ने : सीएम योगी

**गोरखपुर(जीकेबी)**। प्रो. शिवाजी सिंह के निधन पर सीएम योगी ने शोक जताते हुए दुख व्यक्त किया है। परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि शिवाजी सिंह ने अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय इतिहास लेखन को भारत केंद्रीय दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं आचार्य प्रो. शिवाजी सिंह का असामयिक निधन हो गया। इनके निधन पर सीएम योगी ने शोक जताते हुए दुख व्यक्त किया है। परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि शिवाजी सिंह ने अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय इतिहास लेखन को भारत केंद्रीय दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका निधन राष्ट्र एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में भी एक शोक सभा आयोजित की गई थी।

प्रो.राजवंत राव ने कहा कि प्रो. शिवाजी सिंह का निधन न सिर्फ उनके परिवार बल्कि सम्पूर्ण अकादमिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वह एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे। प्रो. शिवाजी सिंह का निधन गुरुवार की सुबह 9:30 बजे के करीब ह्रदय गति रुक जाने के चलते हो गया।

शोक सभा में उन्हें याद करते हुए प्रो.राजवंत राव ने कहा कि प्रो. शिवाजी सिंह एथेन्स में रिसर्च फेलो रहे।

उन्होंने आचार्य राजबली पांडेय के निर्देशन में मनुस्मृति पर शोध कार्य किया था। वह इतिहास के अध्ययन की पूर्णता के लिए साहित्य और पुरातत्व दोनों का अध्ययन आवश्यक मानते थे।

वह गहरी अकादमिक रुचि और अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व पर उनका समान अधिकार था। न्यू आर्कियोलॉजी में उनकी विशेषता थी।

कचहरी में लगी नए कानून की पाठशाला

# बुजुर्ग दिग्गज भी कर रहे पढ़ाई, रट रहे धाराएं

**गोरखपुर(जीकेबी)**। तकरीबन 50 साल बाद दीवानी कचहरी में एक बार फिर कानून की किताबों में ताकझांक होने लगी है। अधिवक्ताओं के टेबल पर नजर दौड़ाएं तो कानून की दो तरह की किताबें नजर आती हैं। एक नए तो एक पुराने कानून वाली। साथ ही नजर आते हैं इन किताबों पर नजर जमाए अधिवक्ता। मंगलवार को कचहरी में दिनभर नए और पुराने कानून की गूंज ही सुनाई देती रही।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मानें तो 1973 में नए कानून के लागू होने के बाद भी ऐसे ही हालत थे। हर तख्ते पर दो-दो किताबें। वारदात को लेकर दो तरह की धाराओं का जिक्र। घटना कब की है, दस्तावेज तैयार करने में पीड़ित से सवाल-जवाब। वारदात की जो धाराएं जुबान पर रहती थीं, अब उसके लिए कानून के जानकारों को कानून की किताब का सहारा लेना पड़ रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज शाही के तख्ते पर कुछ फरियादी और तीन-चार जूनियर अधिवक्ता मौजूद थे। अधिवक्ता विनोद कुमार आजाद मारपीट के एक केस से संबंधित कागजात तैयार कर रहे थे। धारा पर आकर अटक गए। सहयोगी से बोले-जरा बीएनएस की किताब में देखो कि नए कानून के तहत कौन सी धारा लगेगी। अब तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वरना आईपीसी की धारा ही अभी याद है। कानून के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता रमापति शुक्ल बताते हैं - 1968 में कानून में बदलाव हुआ था। उस दौरान मेरी प्रैक्टिस करीब पांच साल की थी। कुछ दिनों तक परेशानी होती है। हम लोगों ने कानून की किताब का पूरा अध्ययन किया था। आज नए अधिवक्ताओं को भी चाहिए कि वे नए कानून को पहले पढ़ें। चुनौतियां तो आती हैं पर धीरे-धीरे अभ्यास में आ जाएगा। अधिवक्ता कृष्ण दीपक ने कहा-अचानक हुए बदलाव के कारण इसे रट पाना आसान नहीं होगा। कागजात तैयार करते समय अभी आईपीसी की धारा ही लिख दे रहा हूं। यह गलती होने की वजह से बार-बार नए पेपर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अभी एक प्रार्थनापत्र बनाना था, उसमें पुरानी धारा का उल्लेख हो गया था, जबकि घटना दो जुलाई की थी। फिर प्रार्थनापत्र फाड़कर दूसरा लिखना पड़ा। तभी वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज शाही आए, उन्होंने प्रार्थनापत्र को दोबारा चेक किया। इसके बाद उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि कानूनी काम में लिखा-पढ़ी में छोटी-छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। कहीं गलती हो जाए तो केस पर उसका असर पड़ता है। दोपहर दो बजे के करीब दीवानी कचहरी में लंच हुआ था। अधिकतर अधिवक्ता उस समय कैंटीन में चाय-नाश्ते के साथ बीएनएस पर ही चर्चा करते दिखे। वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र द्विवेदी अपने एक-दो जूनियर को बीएनएस की नई किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठाए हुए थे। उन्होंने कहा-नए मुकदमे को दाखिल करने में दिक्कत आएगी। मेरे पास एक नया मामला था, लेकिन समझ में नहीं आया तो उसे दाखिल नहीं किया। कोर्ट में जिरह के समय भी अधिवक्ता आपस में मजाक कर रहे हैं कि नया वाला है कि पुराना मामला है।

वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मैंने कानून की पढ़ाई पूरी कर 1987 में वकालत शुरू की। मेरे सीनियर बताते थे कि जब 1973 में कानून में संशोधन हुआ था, तब भी बहुत असमंजस जैसी स्थिति थी। हालांकि, उस समय आंशिक संशोधन ही हुआ था। अब कई अहम धाराएं बदल गई हैं। वर्तमान में एक जुलाई से लागू नए आपराधिक कानून को जानने एवं समझने के लिए सभी अधिवक्ताओं को दोनों कानून के फर्क को समझना पड़ेगा। इसके लिए पढ़ने की जरूरत है, ताकि दस्तावेजों को तैयार कर करने में असहजता न आए। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दूबे ने बताया कि आईपीसी की सभी धाराएं याद हो गई थीं। उसी के अंतर्गत सभी केस देखता था। बहुत कम ही ऐसा होता है कि किताब देखनी पड़ी हो। मुवक्किल जैसे ही घटना के बारे में बताते हैं, प्रार्थनापत्र सुसंगत धाराओं में तैयार करवा देता था। अब नया कानून आने के बाद असमंजस तो है। कई बार किताबें देखनी पड़ रही हैं। अगर गलत हो जाए तो अर्जी ही खारिज हो जाएगी।

## मोहद्दीपुर बिजली उपकेंद्र हुआ 'स्मार्ट'

# एसई ने किया उद्घाटन- शुरू हुआ फीडर पर लगा 'मीटर'

**गोरखपुर(जीकेबी)**। मंगलवार को शहरी मंडल के मोहद्दीपुर उपकेंद्र के फीडरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाया गया। इस मीटर को एनएफएमएस सिस्टम के जरिए राज्य व केंद्रीय मुख्यालय से भी जोड़ा गया है। इससे बिजली खपत की निगरानी सीधे केंद्रीय ऊर्जा विभाग भी कर सकेगा।

अधीक्षण अभियंता शहरी लोकेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अब उपभोक्ताओं के घर के साथ-साथ बिजली उपकेंद्र में फीडरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इसे एनएफएमएस सिस्टम के जरिए राज्य व केंद्रीय मुख्यालय से भी जोड़ा जा सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि मुख्यालय के अफसर भी किसी फीडर के लोड और आपूर्ति की जानकारी ले सकेंगे। ग्रामीण मंडल के खोराबार में सोमवार को स्मार्ट मीटर लगाने के बाद मंगलवार को एसई के निर्देश में बिछिया समेत अन्य तीन फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं।

स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिस कंपनी को मिला है, उसने सबसे पहले खोराबार उपकेंद्र में पहला मीटर लगवाया है। अब ये शहरी क्षेत्र में भी अभी बिजली

उपकेंद्रों के फीडरों पर मीटर लगा रहे हैं।

सभी बिजली घर के फीडरों पर मीटर लगाने के बाद फिर उपभोक्ताओं के परिसर पर भी मीटर लगाए जाने शुरू होंगे।

मैनेजर राकेश सिंह ने बताया कि भारत सरकार की स्मार्ट मीटर योजना के तहत यह कंपनी प्रदेश के कई और जिलों में भी स्मार्ट मीटर लगाएगी। गोरखपुर में सीई और एसई के निर्देशन में मीटर लगाने का काम फर्म की तरफ से किया जा रहा है। बताया कि इस मीटर से नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए फीडर को जोड़कर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से भी इसकी निगरानी की जा सकेगी।

# सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की तैयारियों का किया निरीक्षण किया

**गोंडा (जीकेबी)**। आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर घाघरा नदी पर एली परसौली तटबंध और एल्गिन ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल जिले में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आदित्यनाथ ने कहा कि जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने सभी एहतियाती इंतजाम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग ने जिले के एल्गिन-चरसड़ी, भिखारीपुर-सकरौर, परसपुर-धौरहरा और भौरीगंज रिंग बांध के चारों तटबंधों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन ने 28 बाढ़ चौकियां भी स्थापित कर दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य, पशुपालन और राजस्व विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं... बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावें तैयार हैं। आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने बाढ़ की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की चेतावनी दी। संभावित बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में प्रभावित इलाकों में मोबाइल मेडिकल टीमें सक्रिय रहें।

# हल्की बारिश में भी जलभराव की स्थितियों से दोचार होते महानगरवासी

**गोरखपुर (जीकेबी )**। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का शहर ही नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर है। इसके पूर्व वह लगातार यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार विधायक बने और दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शहर का मेयर लगातार भाजपा का ही हो रहा है। बोर्ड में भाजपा के ही लोगों का बहुमत है। नगर पालिका क्षेत्र के नालों की सफाई जल निकासी सड़कों की मरम्मत एवं पथ प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसके लिए लम्बी धनराशि शासन से मिल रही है। बरसात के काफी पहले शासन एवं नगर निगम का यह प्रयास होता है कि नालों की सफाई करवा दी जाए लेकिन इस सत्र के पहले ही बरसात ने नगर निगम की नालों की सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था का सारा पोल खोल कर रख दिया। आज हमारे संवाददाता ने घोषकंपनी चौराहा, रेतीरोड, जिला अस्पताल का गेट, कचहरी चौराहा, कलेक्टरी कचहरी के अन्दर, धर्मशाला बाजार पुल के नीचे, अली नगर, रुस्तमपुर ढाला, महुई सुघरपुर, राजीवनगर, मिर्जापुर, हुमायुंपुर, रेलवे कालोनी

पत्रकारपुरम, दिग्विजयनगर, गोरखनाथ, जमुनहिया बाग, जाहिदाबाद, हड़हवा फाटक नवीन गल्ला मंडी के पीछे वाली सड़कों आदि क्षेत्रों में हल्की सी बारिश के बाद जलजमाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।

15 जुलाई 2018 को योगी आदित्य नाथ की सरकार ने पाली थीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए चरणवार लागू करने का खाका रखा था। पहले चरण में- शहरी क्षेत्रों में पालीथीन के भंडारण निर्माण बिक्री और आयात-निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। दूसरे चरण में 15 अगस्त 2018 से पाली थीन और थर्मोकोल समेत सिंगल यूज्ड प्लास्टिक प्रतिबंधित किया। 2 अक्टूबर 2018 से सभी प्रकार के पालीथीन बैग प्रतिबंधित किये। लेकिन सरकारी तंत्र ने इसे अनदेखा कर दिया। पिछले सप्ताह ही नगर निगम की टीम ने साहबगंज के व्यापारी के यहां से 600 कुंतल प्रतिबंधित पाली थीन जब्त करने में सफलता प्राप्त की थी। प्रवर्तन दल हर सप्ताह ही पाली थीन जब्त कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना बताता है कि प्रतिबंधित पालीथीन की डिमांड कम नहीं हुई है।
नगर निगम गेट के समीप में ही बैं क रोड पर मामूली बरसात के बाद ही पानी भर जाता है। इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर निगम के लोग नहीं लेते हैं।

## नेपाल का सत्ता संघर्ष

दरअसल, नेपाल एक बार फिर तीन दावेदारों के बीच सत्ता सेघर्ष का साक्षी बन रहा है। दहल ने नेपाली काग्रेस के साथ अपना गठबंधन खत्म किया, जो नेपाली संसद में सबसे बड़ी पाटी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के साथ हाथ मिलाया, जो संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दहल की पाटी नेपाली संसद के निचले सदन में तीसरी सबसे बड़ी पाटी है। नेपाल इस कहावत का शानदार उदाहरण है कि राजनीति संभावनाओं का एक खेल है। नेपाल की दो सबसे बड़ी पार्टियां, जो वैचारिक रूप से एक -दूसरे की धुर विरोधी हैं, सरकार बनाने के लिए एकजुट हो रही हैं। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) ओली के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सहमत हो गई हैं। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में दोनों की संयुक्त ताकत 167 है, जो 138 के बहुमत के अकड़े से ज्यादा है। इसका मतलब 18 महीने पुराने प्रचंड के शासन का अंत हो सकता है, जिनहोंने कभी नेपाली काग्रेस, तो कभी सीपीएन (यूएमएल) के समर्थन से इस अवधि के दौरान तीन बार सरकार का नेतत्व किया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने पुष्टि की कि सत्ता साझा करने पर सहमति पिछले सोमवार को ही बन गई थी। सीपीएन (यूएमएल) के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा, केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में राष्ट्रीय सर्वसम्मति वाली सरकार बनाने के लिए यूएमएल और नेपाली कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। नेपाल में हिमालय और भगवान पशपतिनाथ को शाश्वत माना जाता है। लेकिन न तो हिमालय की मौजदगी और न ही भगवान पशूपतिनाथ का आशी्वाद नेपाल में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चत कर सका है। लालची नेताओं के आपसी संघर्ष ने एक और सरकार को खतरे में डाल दिया है। राजशाही के खत्म होने और नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की 13वीं सरकार पर विद्रोह का खतरा मंडरा रहा है। उप प्रधानमंत्री और बनियादी संरचना व परिवहन मंत्री रघुबीर महासेठ ने प्रधानमंत्री दहल को अपना इस्तीफा सौप दिया है। जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल के समर्थन वापस लेने के बाद जब 20 मई को दहल ने तीसरी बार विश्वास मत हासिल किया था, तो 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में उन्हें 157 वोट मिले थे। अब यूएमएल के समर्थन वापस लेने से उनमें से 7 वोट घट गए हैं । हालांकि दहल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और अब वह नेशनल असेंबली में विश्वास मत की मांग करेंगे। हालांकि वह पहले तीन बार विश्वास मत हासिल कर चुके हैं, लेकिन नेपाल के सियासी भंवर में यह पर्याप्त नहीं है। वास्तव में 2008 के बाद से इस हिमालयी देश में सभी सरकारें दो या दो से अधिक पार्टियों की गठबंधन वाली रही हैं. जिनमें सहयोगी और विरोधी दल बारी-बारी से अपनी स्थिति बदलते रहे हैं । एक बार फिर सियासी घमासान मचा है। 69 वर्षीय दहल, जो तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, के अलावा 72 वर्षीय खड़ग प्रसाद शर्मा ओली दो बार, तो 78 वर्षीय शेर बहादुर देउबा रिकॉर्ड पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बहमत दिखाने के लिए विश्वास मत हासिल करने की खातिर संविधान के तहत दहल को 30 दिन का संमय मिलेगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी,जिससे स्वाभाविक ही गरीब देश में आर्थिक संकट बढ़ेगा। माओवादी सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा गठबंधन को बचाने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड और सीपीएन-यूएमएल प्रमुख ओली के बीच वा्ता भी विफल हो गई है। काठमांड् से मिल रही जानकारियों के मुताबिक, दहल ने इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन दिवंगत गायक फतेर्मान के एक नेपाली गीत को याद किया- 'येस्तो पानी हंडो रइछा जिंदगी मा कहिले, कहिले (कभी-कभी जिंदगी ऐसे ही सामने आती है)। उन्हॉने कहा, हमने बड़ी शिद्दत से साथ मिलकर काम किया, लेकिन इस बार चीजे बदल गई हैं । हमें भविष्य में भी साथ मिलकर काम करना चाहिए। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य और पूर्व वित्तरमंत्री प्रकाश शरण महत ने भी इसकी पुष्टि की। लिखित समझौते के अनुसार, ओली और देउबा मौजूदा प्रतिनिधि सभा के बचे हुए समय में बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। हालांकि अतीत में ओली ने दहल के लिए पद छोड़ने से इन्कार कर दिया था। नेपाल में पिछ्ला संसदीय चुनाव नवंबर, 2022 में हुआ था, इसलिए अभी मौजूदा सदन का कार्यकाल साढ़े तीन साल बचा हुआ है। दहल के समर्थकों का कहना है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों को रोकने के लिए दहल के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। बीती एक जुलाई को दहल और गृहमंत्री रबी लामिछाने ने कहा था कि भ्रष्टाचार के बड़े घोटालों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग बनाने की तैयारी चल रही है।

## हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने

लगभग 150 दिन मुख्यमत्रा रह चंपाई की सरकार का कामकाज अच्छा ही रहा। उसके बावजूद अचानक नेतृंत्व परिवर्तन की परिस्थितियां झारखंड उच्च न्यायालय के 28 जून के निर्णय से बनीं, जिसमें हेमेंत सोरेन को रिहा करते हुए टिप्पेणी की गई कि उनके विरुद्ध ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। जाहिर है, मनी लॉन्ड्रिग के जिस केस के चलते हेमंत को मुख्यमंत्री पद छोड़कर पांच महीने जेल में रहना पड़ा, उसमें उच्च न्यायालय के मुताबिक कोई साक्ष्य न होना, इण्डिया ब्लॉक के लिए नैतिक जीत ही नहीं, बडा राजनतक हथियार भी बन सकता है। इसीलिए संसद सत्र के दौरान ही सोनिया गांधी समेत'इंडिया' ब्लाक के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हेमंत से बात करके उनके पुनः मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया। झामुमो समेत पूरे 'इंडिया' ब्लॉक को लगता है कि अगर मनी लॉन्डिंग केस में जेल में रहते हुए इतनी सहानुभूति मिली कि भाजपा की सीट के साथ- साथ मत-प्रतिशत भी घट गया, तो उच्च न्यायालय द्वारा रिहाई के बाद हेमंत के पुनः मुख्यमंत्री बनने से विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित हो जाएगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में 81 सदस्यीय सदन में सत्त-ारूढ़ भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि झामुमो 30 और कांग्रेस 16 सीटें जीतने में सफल रहे थे। राजद को भी एक सीट मिली थी। हालिया लोकसभा चुनाव में सीटें और मत-प्रतिशत बढ़ने से उत्साहित 'इडिया ब्लॉक को लगता है कि साक्ष्यों के अभाव में रिहा हेमंत गठबंधन के नेता के रूप में जनता के बीच जाएंगे, तो सहानुभूति चरम पर पहुंच सकती है।

अपनी विनम्रता और सादगी के लिए लोकप्रिय चंपाई ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे का कारण 'इंडिया ब्लॉक के फैसले को बताते हुए टिप्पणी की : 'हमें जो जिम्मेदारी दी गई, हमने निभाई। अब हेमंत बाबू वापस आ गए हैं।' लेकिन विरोधियों की रणनीति इसे आदिवासी बुजुर्ग के अपमान और सोरेन के परिवारवाद के रूप में पेश करने की है। बेशक राजनीतिक दलों व नेताओं को अपने चुनावी मुद्दे तय करने का अधिकार है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि अपने मुद्दे चुनकर जनादेश देना मतदाताओं का विशेषाधिकार है। अरसे से झारखंड में सत्ता के लिए जारी शह-मात के खेल में अंतिम निर्णय जनता जनार्दन का ही होगा। मगर एक पेच बाकी है। उच्च न्यायालय के फैसले को प्रवर्तन निदेशालय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। वहाँ से झटका लगा, तो हेमंत क्या करेंगे ? क्या इस बार कल्पना को उत्तरधिकारी बनाएंगे, जो इस बीच दिल्ली में विपक्ष की रैली और लोकसभा चुनाव में प्रचार के अलावा उप-चुनाव जीतकर विधायक भी बन चुकी हैं ? साहिर के उसी गीत की यह पंक्ति भी सबको याद रखनी चाहिए :आदमी को चाहिए, वक्त से डरकर रहे।

वैसे तो हेमंत ऋतु दिसंबर में आती है, पर झारखंड में 4 जुलाई को ही हेमंत-राज की वापसी हो गई। गुरुवार की शाम शपथ ग्रहण कर हेमंत सोरेन झरखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन गए। झाखड का नाटकीय घटनाक्रम 1965 में आई हिंदी फिल्म वक्त के चर्चित गीत को चरितार्थ करता है। मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए साहिर लुधियानवी के उस गीत की पंक्ति है- कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज ।

इसी साल जनवरी के अंतिम दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) द्वारा मनी लॉन्डिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने से पर्व हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब अटकलें थीं कि वह पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हेमंत ऐसा करते, तो विरोधियों को आसन्न लोकसभा चुनाव के लिए उनके विरुद्ध परिवारवाद का मुद्दा मिल जाता, पर उन्होंने वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपाई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर विरोधियों की रणनीति नाकाम करते हुए सबको चौंका दिया।

कोल्हान के 'टाइगर' कहे जाने वाले उन्हीं चंपाई ने अब इस्तीफा देकर हेमंत के फिर से मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया। जाहिर है, इसे वरिष्ठ आदिवासी नेता का अपमान बताते हाए उनके राजनीतिक विरोधी विधानसभा चुनाव में सोरेन परिवार पर सत्ता की भूख का आरोप लगाएंगे। 'इंडिया' ब्लॉक को आशंका है कि अक्तूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव हो सकता है। उन चुनावों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से किसके दांव-पेच मतदाता को मोह पाए, यह तो नतीजों से पता लगेगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि झारखंड़ आंदोलन के अगुवा रहे अपने पिता शिब्बू सोरेन की छाया से निकलकर हेमंत एक समझदार और जिम्मेदार राजनेता की छवि बनाने में सफल रहे हैं।

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटे राजग द्वारा जीत लिए जाने के बावजूद चंद महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार बना लेना हेमंत सोरेन की बड़ी सफलता थी, लेकिन उनके राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा तो पिछले दो साल में अपनी सरकार के बचाने की कवायद में हुई। अपने दल झारखंड मुक्त मोर्चा में टूट की आशंका के चलते उन्हें विधायकों को लेकर राज्य से बाहर भी जाना पड़ा।

कथित भूमि घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज केस में गिरफ्तारी से जब सरकार गिरने की आशंका गहराई, तब हेमंत खुद इस्तीफा देकर और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर उसे टालने में सफल रहे। कानूनी सलाह के लिए दिल्ली जाने पर 'भगोड़ा करार देने वाले विरोधियों का अनुमान था कि वह आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे, और अगर दिया भी, तो पत्नी को कुर्सी सौंपेंगे। दोनों ही स्थितियों में विरोधियों के तरकश में जोरदार राजनीतिक और चुनावी हथियार आ जाते, पर हेमंत ने बता दिया कि आदिवासी भोलेपन का अर्थ नासमझ होना नहीं है। इस्तीफे से पहले विधानसभा में उनका भाषण जबदस्त था, जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर साजिश रचने के आरोप लगाते हुए चुनौती भी दी थी। हेमंत के जेल में रहते हुए झामुमो को तोड़ने की कोशिशें की खबरें आती रही उनकी भाभी सीता स्वयं भी टूट गई । भाजपा ने दुमका से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया लेकिन हार हाथ लगी। लोकसभा चुनाव परिणामों ने बता दिया कि खासकर आदिवासी बहुत क्षेत्र में सहानुभूति हेमंत के साथ है। 2019 में 11 सिम जीतने वाली भाजपा इस बार 8 पर रह गई जबकि आदिवासियों के लिए आरक्षित पांच सभी सिम इंडिया ब्लॉक की झोली में गईं ।

## सरकार को संसाधनों में मेहनतकशों के हिस्से को सुनिश्चित करना होगा

अभी 20 जून को की सचिव सुमिता डावरा ने देश भर के सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के श्रम सचिवों व श्रमायुक्तों के साथ दिल्ली में बैठरकी है। जैसी कि रपट है कि इस बैटक में केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाई गई 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के संबंध में सभी राज्यों को निर्देश दिया है। राज्यों से कहा गया है कि वह केन्द्र के द्वारा बनाई गई श्रम संहिताओं के अनुरूप अपने राज्यों में नियमावली बनाए।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, मेधालय, नागालैंड, लक्ष्यद्वीप , सिक्रिम, अंडमान निकोबार और दिल्ली ऐसे राज्य व केनद्र शासित क्षेत्र हैं जिन्होंने अभी तक पूरी नियमावली नहीं बनाई है। सरकार के वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि कई राज्यों द्वारा बनाईगई नियमावली केन्द्र सरकार द्वारा बनाई श्रम संहिताओं और उनकी नियमावली की मूल भावना के ही विरूद्ध हैं। इसलिए इनको बदलना होगा और केन्द्र के अनुरूप बनाना होगा। 2020 में संसद से पारित इन संहिताओं को केंद्र सरकार अतिशीघ्र लागू कराने में लगी है। 100 दिन के एजेंडे और टास्क में भी केन्द्र सरकार ने इसे रखा है। यह जो, नई श्रम संहिताएं बनाई गई हैं उनमें साफप्रावधान कियां गया है कि काम के घंटें 12 किए जाएंगे। इसके चलते करीब 33 प्रतिशत उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की अनिवार्य रूप से्टनी हो जाएगी। इतना ही नहीं 12 घंटे काम के होने के बाद मजदूरों को नित्य कर्म के लिए करीब 1718 घंटा काम करना पडेंगा इसके कारण उनकी शारीरिक अवस्था पर भी बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा और बेहद कम उम्र में ही ब्लड़ प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस जैसी तमाम बीमारियों का उन्हें शिकार होना पड़ेंगा। इन श्रम सहिताओं में यह प्रावधान किया गया है कि अभी चल रही न्यूनतम मजदूरी की जगह फ्लोर लेवल मजदूरी लाई जाएगी। इसका मतलब है कि किसी तरह अपने चार युनिट पंरिवार को जिसमें पति-पत्नि और दो बच्चे शामिल हैं, उनके खाने, पीने, पहनने के कपड़े के लिए जो न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है उसे भी कम करके फ्लोर लेवल मजदूरी तय की जायेगी जिससे इस भीषण महंगाई में किसी तरह अपने परिवार की जीविका चलाने वाले मजदूर की जिंदगी बेहद कठिन हो जायेगी। नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों के आने के 33 सालों में पूरे देश में ठेका प्रथा ने विशाल स्वरूप ग्रहण कर लिया है। देश की संसद से लेकर कारखाने तक और यहां तक की टीचरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, नसों, कम्प्यूटर आपेरेटरों आदि के प्रोफेशनल क्षेत्र में भी ठेका प्रथा लागू की जा रही है। इस प्रथा का सिर्फ एक मकसद था श्रम शक्ति की भयकर लूट को अंजाम देना। जो काम स्थाई मजदूर से ज्या
करके और उसकी जीवन सुरक्षा को सुनिश्चित करके कराया जाता था
ठेका प्रथा में बेहद कम मजदूरी पर कराया जा रहा है। नई श्रम सहिता में
प्रथा से भी बदतर फिक्स टर्म इम्पलाइमेंट को लाया गया है। माने कुछ अ
मजदूरों को काम पर रखा जाएगा और उनके ऐसे काम में इपीएफ ईएस
पेंशन, ग्रेच्यूटीं आदि तमाम सुविधाएं नहीं रहेगा। ठेका मजदूर कानून 19
जो स्थाई कामों में ठेका प्रथा से नियोजित करने पर रोक लगी हुई थी उसे
खत्म कर दिया गया। यहां तक की समान काम के समान वेतन के प्रावधान
दिया गया है देश में इस समय 95 फीसदी मजदूर असगठित क्षेत्र में काम
कोरोना महामारी के समय इन मजदूरों की दुर्दशा को सभी ने करीब से देख
यह राष्ट्रीय मुद्दा भी बना था उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद -
का निर्माण किया गया। इसमें खेत एवं ग्रामीण मजदूर, मनरेगा, निर्माण, परल्

वाहन चालक, कुली, पल्लेदार, रिक्शा टेला वाले, बुनकर वं चिकनकारी समेत कटीर और लघु उद्योगों में काम करने वाले, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा कर्मी, मिड डे मील, ईंट भटठा, खनन आदि क्षेत्रा में काम करने वाले मजदूर हैं। यह वह मंजदूर हैं जो ईपीएफ और ईएसआई के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे देश में करीब 28 करोड़ मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हुआ है। उत्तर प्रदेश में यह संख्या करोड़ 30 लाख है। इन मजदूरों की सामजिक सुरक्षा के लिए बार वार सप्रीम कोर्ट के निदेर्शों के वावजूद अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। हालात यह है कि ऐसे असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 2005 में संसद से सामाजिक सुरक्षा कानून बनाया गया था जो आज भी लागू होने के इंतजार में है। इन मजदूरों में 93 फीसद मजदूर 10 हजार रुपए से कम पर अपने परिवार की जीविका चला रहें हैं। इसके अलावा जो संगठित क्षेत्र है भी उसमें बड़ी संख्या ठेका/संविदा या आउटसोसिंग मजदूरों की है, यह भी अल्य वेतन पर ही आजीविका चला रहें हैं। उत्तर प्रदेश में तो पिछले पांच साल से न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन न होने से मजदूरों का वेतन बेहद कम है और इस महंगाई में परिवार की जीविका चलाना बहत कठिन हो गया है। श्रम संहिताओं में निर्माण, बीड़ी, खनन आदि जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बोर्ड बनाकर स्कीम लागू करने के प्रावधान थे उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। श्रम विभाग की जो प्रवर्तन यानी एनफो्समेंट की शक्तियां थी उन्हें

बदलकर फैसिलिटेटर यानी सुगमकर्ता बना दिया गया है। स्वाभावतः श्रम विभाग की भूमिका मालिकों की सुविधाओं को सुगम बनाना होगा। मजदूरों के हड़ताल आदि पर वहुत सारी कानूनी अड़चनों को श्रम संहिताओं में खड़ा कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन का गठन करना भी बेहद कठिन हो जाएगा और जो पंजीकृत यूनियन है उनका रजिस्ट्रेशन कैसिल करना आसान बन जाएगा। सरकार और उसके संस्थान कैसे मालिकों और कारपरेट घरानों के लिए सुगाम रास्ता बना रहे हैं इसका एक उदाहरण सामने है सत में आते ही सरकार ने इंपीएफ के नियमों में बदलाव कर दिया और जमार्ना धनराशि को बेहद कम कर दिया है। दरअसल देशी विदेशी कारपोरेट घरानों के अकूत मुनाफे के लिए जिन नई श्रम संहिताएं को लेकर सरकार आई है ससे देश में कार्यरत मेहनतकश की जीवन व सामाजिक सुरक्षा. वकिंग कडीशन, वेतन आदि में आमूल चूल परिवर्तन जायेगा जिससे पहले से ही बढ़ रही भयंकर बेरोजगारी में और वृद्धि होगी यही नहीं यह रास्ता देश में बड़ी औद्योगिक अशांति को भी पैदा करेगा क्योकि लेवर ला और श्रम विभाग की भूमिका औद्योगिक शांति कायम करने में महत्वपूर्ण थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी सरकार जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है वह पूंजी के आदिम संचय का रास्ता है इससे मजदूरों की तबाही होना सुनिश्चित है। इन नीतियों के कारण मेहनतकश मनुष्य से वस्तु (माल) में तब्दील होकर आधुनिक गुलामी में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होगा। मजदूरों की जिदंगी की हिफाजत के लिए आज इस रास्ते को बदलना ही होगा। सरकार को संसाधनों में मेहनतकशों के हिस्से को सुनिश्चित करना होगा।

वास्तव में आज देश में प्रति व्यक्ति आय एक लाख 70 हजार रूपए वारषिक है। लेकिन देश के 93 फीसदी मेहनतकश परिवार 10 हजार रुपए प्रतिमाह से कम में जीविका चलाते हैं। जबकि देश का खजाना आम जनता के टैक्स से भरता है। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी और पेट्रोलियम पदाथों में टैक्स का 97.6 फीसदी देश का 90 प्रतिशत गरीब और मध्य वर्ग देता है। वहीं देश का 10 फैसदी उच्च वर्ग टैक्स में 2.4 प्रतिशत देता है। यानी कल प्राप्त 2748718 करोड़ में से 2682748 करोड़ रूपए 90 फैसदी आम आदमी जमा करता है और उच्च वर्ग महज 65969 करोड़ रुपए का योगदान देता है।

आम आदमी से प्राप्त धन में मात्र 5 लाख करोड रूपए ही सरकार मनरेगा, मुफ्त राशन, शिक्षा-स्वास्थ्य आदि सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र पर खर्च करती है। स्पष्टतः देश की आय का बड़ा हिस्सा कारपोरेट घरानों द्वारा हड़प लिया जा रहा है। इसने देश में असमानता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का काम किया है।

विश्व असमानता लैब की रिपोर्ट के अनुसार इस समय मोजूद असमानता 1922 में पैदा हुई असमानता से भी ज्यादा है और ऊपरी 10 फीसद लोगों के पास देश की सम्पत्ति का 65 प्रतिशत और आय का 57 प्रतिशत हिस्सा है। इसलिए मजदर वर्ग को आने वाले समय में सामाजिक व जीवन सुरक्षा, मजदर विरोधी नए लेवर कोड की हर हाल में समाप्त, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि देश की आय और संसाधनों में हिस्सेदारी के लिए एक बड़ी राजनीतिक पहल के लिए अपने को तैयार करना होगा।

## नए चेहरों से सजा मंत्रिमंडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार के 36 मंत्री नई सरकार में दिखाई नहीं देंगे। जबकि 38 नए मंत्री बनाए गए हैं प्रधानमंत्री ने सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। नए मंत्रियों में ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा 27 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि सवर्ण समुदाय से 25, एससी और एसटी से 14 व पांच अल्पसंख्यक मंत्री हैं। सरकार में गठबंधन का दबदबा बढ़ा है और 11 मंत्री पद भाजपा के 9 सहयोगी दलों को मिले हैं। इनमें टीडीपी को दो, जदयू को दो, जदएस, अपना दल, शिवसेना, लोजपा (रामविलास), हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, आरपीआई और आरएलडी को एक-एक मंत्री पद दिया गया है। नई सरकार में प्रधानमंत्री समेत 31 कैबिनेट मंत्रियों में भाजपा के पास 26, स्वतंत्र प्रभार के पांच एवं राज्य मंत्रियों में तीन मंत्री हैं। जबकि 35 राज्य मंत्रियों में 32 राज्य मंत्री भाजपा के हैं। सहयोगी दलों में जिन नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उनमें जदएस के एचडी कुमारस्वामी, हम के जीतनराम मांझी, जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, टीडीपी के राम मोहन नायड और लोजपा रामविलास के चिराग पासवान शामिल हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में शिवसेना के प्रताप राव जाधव और रालोद के जयंत चौधरी को मंत्री बनाया गया है। जबकि राज्य मंत्रियों में रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी, रामनाथ ठाकुर जदयू, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, टीडीपी के पी. चंद्रशेखर को जगह मिली है। मंत्रिमंडल में प्रमुख जाट चेहरा राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रीमंडल में युवा जोश और अनुभव का तालमेल बनाने की कोशिश की है। नई सरकार में युवाओं को तरजीह दी गई है, लेकिन वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को खासा महत्व भी दिया गया है। पिछली सरकार के अधिकांश बड़े चेहरे नए मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए हैं। इनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस. जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस बार सरकार में शामिल किया गया है।

प्रथानंत्री नरेन्द्र सोदी की अगवाई राजग सरकार इस बार बदली हुई नजर आएगी क्योंकि, उन्होंनि अपने मत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने पहलीबार कहा कई निवर्तमान मंत्रियो को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, तो राजग के घटक दलो के मंत्रियों की संख्या भी बढ़ाई है। वहीं, पुरानी सरकार के कई बड़े मंत्रियों की इस सरकार में जगह नहीं मिली।

नई सरकार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल के साथ सहयोगी दलों के एचड़ी कुमारस्वामी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जीतन राम मांझी, राम मोहन नायडू और चिराग पासवान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अन्नपूर्णा देवी की पदोन्नति किया गया। पिछली सरकार की राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को इस बार पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। महिला मंत्रियों की संख्या सात है। बगैर किसी सदन का सदस्य बने मंत्री बनने वाले पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू हैं। इसके अलावा, केरल के जॉर्ज कुरियन को भी भाजपा ने मंत्री बनाया, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। सरकार को मजबूती देने के लिए इस बार कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह मिली है, जिनको पहली बार सरकार में शामिल किया गया है। प्रथानंत्री नरेन्द्र सोदी की अगवाई राजग सरकार इस बार बदली हुई नजर आएगी क्योंकि, उन्होंनि अपने मत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने पहलीबार कहा कई निवर्तमान मंत्रियो को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, तो राजग के घटक दलो के मंत्रियों की संख्या भी बढ़ाई है। वहीं, पुरानी सरकार के कई बड़े मंत्रियों की इस सरकार में जगह नहीं मिली।

विभिन्न समीकरणों के चलते अनुराग ठाकुर, नारायण राणे और अजय भट्ट को नई सरकार में जगह नहीं मिली। वहीं, प्रधानमंत्री ने राजग के सहयोगी दलों के कई सांसदों को अपनी सरकार में जगह दी है। इनमें जद (यु) नेता राजीव रंजन सिंह ललन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी शामिल हैं। इसके साथ टीडीपी के मंत्री भी शामिल हैं प्रधानमंत्री मोटी ने अपनी सरकार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल को भी शामिल किया है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियो ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि, शिवराज इससे पहले भी कई बार लोकसभा सांसद रह चुके है। प्रथानमंत्री ने पिछली सरकार में शामिल रहे राज्यमंत्री को तरक्की भी दी है। झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा दैवी को तरक्की देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है प्रधानमंत्री ने सबसे कम बदलाव राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) में किया वहीं सबसे ज्यादा बदलाव राज्य मंत्रियों में किया प्रधानमंत्री ने कई सांसदों को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी।

# जनमत चाहे जैसा भी हो उसे सम्मान से स्वीकार करें

उपरोक्त जनादेश निश्चित रूप से न केवल मंहगाई, बेरोजगारी, साम्प्रदायिकता तथा धर्म के नाम पर समाज को विभाजित कर जन सरोकार के मूल मुद्दों से जनता जनार्दन का ध्यान भटकाकर उसे धार्मिक भावनाओं में उलझाकर रखने के विरुद्ध था बल्कि यह जनादेश जनता द्वारा सत्ता का घर्मंड चूर कर देने के लिये भी था। परन्तु जनता के हाथों अपनी मुंह की खाने वाले भाजपाइयों को जो 400 पार और 370 पार जैसे नारों में जी रहे थे उनहें यह जनादेश कतई नहीं भाया। इसलिये न केवल अंधभक्तो ने बल्कि साम्प्रदायिक विद्वेष के बल पर अपनी नैय्या पार करने की इच्छा पाले कई पराजित उम्मीदवारों ने भी मतदाताओं को ही गरियाना शुरू कर दिया।

अयोध्या फैजाबाद के मतदाताओं को इतना कोसा गया व उनके लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मानो इस लोकसभा सीट की भाजपा ने अपने नाम 'रजिस्ट्री' ही करा ली थी जिसे जनता ने छीन लिया। आखिर अयोध्या की जनता ने किन कारणों से यह जनादेश दिया? क्या 'जो राम को लाये हैं हम उनको लायेंगे' जैसा नारा जो भाजपाई लगाते फिर रहे थे वह नारा पूरे देश का सर्वस्वीकार्य नारा है? क्या शंकराचार्यों से लेकर अयोध्या के साधू संत तक इस अहंकारी नारे से सहमत हैं? अब तो लोग यही मान रहे हैं कि भगवान राम ने ही अहंकारियों को आईना दिखाया है और चेताया है कि धर्म किसी भी व्यक्ति की निजी आस्था व विश्वास का विषय है राजनीति व सत्ता के लिये दुरूपयोग का नहीं। इसी तरह रायबरेली की जनता के हाथों पराजित भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह तो अपनी शर्मनाक पराजय से रायबरेली के मतदाताओं से इतना आग बबूला हुये कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वे 'एक वर्ष के अवकाश पर रहेंगे और रायबरेली की जनता कों कोई काम ही नहीं करेंगे। जिसे काम कराना हो वह राहुल गाँधी के पास ही जाएं।

जनादेश 2024 तो जरूर आ चुका है परन्तु षड़यंत्रकारी एक्जिट पोल की हवा निकलने के बाद आये आश्चर्यचकित करने वाले इस जनादेश ने खास तौर पर उन लोगों के मुंह का स्वाद बिगाड़ कर रख दिया है जो ' अबकी बार 400 पार जैसे फर्जी नारों और मोदी मीडिया द्वारा प्रचारित झूठे एक्जिट पोल में दिखाई गयी मोदी के नेतृत्व में भाजपा की धमाकेदार वापसी की पूरी उम्मीद लगाये बैठे थे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस बार के परिणाम कुछ ऐसे आये हैं कि एन डी ए बहुमत के आंकड़ों को पार करने के बावजूद विलाप कर रहा है जबकि बहुमत के आंकड़ों से दूर रहने के बाद भी विपक्षी गठबंधन में जश्न का माहौल है। चुनाव परिणाम जो भी हों परन्तु परिपक्व राजनीति का तकाजा तो यही है कि भारतीय लोकतंत्र में जनमत चाहे जो भी हो जैसा भी हो उस का सम्मान किया जाना चाहिये व उसे विनम्रतापूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए।

इसी तरह साम्प्रदायिकतावादी भक्त जन भाजपा के सपने टूटने के लिए कहीं मुस्लिम मतदाताओं को जिम्मेदार ठहराते हुये अपशब्द कह रहे हैं तो कहीं दलितों व पिछडों को गालियां रहे हैं। सवाल यह है कि क्या देश का मतदाता किसी भी दल या राजनेताओं का गुलाम है जो उनकी इच्छाओं के मतदान करे? क्या यह जरूरी है कि भक्तों, साम्प्रदायिकतावादियों की नजरों में अनुरूप ही जो सबसे जरूरी विषय हो मतदाता भी उसे वैसी ही प्राथमिकता दें? हिमाचल प्रदेश दिल्ली, उत्तरांचल, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा जैसी कई जगहों पर भाजपा ने निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। विपक्षी दलों के नेता उन राज्यों के मतदाताओं को तो गलियां नहीं दे रहे हैं? बल्कि वहां आत्म मंथन की बात कर रहे हैं। एनडीए खासकर भाजपाई नेताओं व अंधभक्तों को भी मतदाताओं को गरियाने या परिणाम पर विलाप करने के बजाय आत्ममंथन ही करना चाहिये। पराजय पर इस तरह का विलाप व मतदाताओं को कोसना व गालियां देना तो दरअसल जनता जनार्दन द्वारा दिये गये जनादेश का अपमान ही कहा जायेगा।

इस बार के चुनाव परिणामों के बाद खासतौर पर कुछ विशेष सीटों पर मिली पराजय या उनके अप्रत्याशित नतीजों के बाद पराजित पक्ष के लोगों ने अपना गुस्सा मतदाताओं पर निकालना शुरू कर दिया है। कई पराजित लोग तो मतदाताओं के निर्णय की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक व तीखी प्रतिक्रिया फैजाबाद संसदीय सीट को लेकर सुनाई दी। इसी लोकसभा सीट के अन्तर्गत अयोध्या विधानसभा क्षेत्र भी आता है जहां निर्मित राम मंन्दिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी न केवल फैजाबाद, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के मतदाताओं से यह आस लगाये बैठी थी कि इसी वर्ष 22 जनवरी को हुये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसे ऐतिहासिक बहमत हासिल होगा। इसी सीट से लल्लू सिंह जो कि बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुडे हैं तथा पांच बार अयोध्या से विधायक और दो बार फैजाबाद लोकसभा सीट से ही लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं वह तीसरी बार भी अति आत्मविश्वास के साथ इसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। परन्तु यहाँ के मतदाताओं ने एक अप्रत्याशित जनादेश देते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अर्थात इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को 54,567 मतों से जिता दिया। केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि चित्रकट, मेहंदीपुर बालाजी, सलासर धाम जैसी और भी अनेक धर्म नगरियां हैं जहाँ भाजपा धर्मध्वजा के सहारे जीत हासिल करना चाहती थी परंतु वैसे सभी क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशियों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हद तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने स्वयं को 'अवतारी' होने का भ्रम पाल रखा था और 2019 के चुनाव में काशी से ही 4 लाख 71 हजार के अंतर से जीत हासिल की थी वे इस बार काग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को 152513 मतों से ही पराजित कर सके। जबकि ऐतिहासिक रोड शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस और गंगा में क्रूज यात्रा जैसी शोबाज़ियों के सहारे वे इस बार 10 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का सपना देख रहे थे। उनका पूरा मत्रिमंडल काशी में उतर आया था। कांग्रेस समाजवादी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में वह धमाका शायद इण्डिया गठबंधन को भी उम्मीद नहीं थी। यहां इण्डिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की। उधर भाजपा द्वारा 'पप्पु' प्रचारित किये गए राहुल गाँधी जहां वायनाड से 3.64 लाख बोटों से जीते वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्री बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से 3.90 लाख वोटों से पराजित किया। उपरोक्त जनादेश निश्चित रूप से न केवल मंहगाई, बेरोजगारी, साम्प्रदायिकता तथा धर्म के नाम पर समाज को विभाजित कर जन सरोकार के मूल मुद्दों से जनता जनार्दन का ध्यान भटकाकर उसे धार्मिक भावनाओं में उलझाकर रखने के विरुद्ध था बल्कि यह जनादेश जनता द्वारा सत्ता का घर्मंड चूर कर देने के लिये भी था। परन्तु जनता के हाथों अपनी मुंह की खाने वाले भाजपाइयों को जो 400 पार और 370 पार जैसे नारों में जी रहे थे उनहें यह जनादेश कतई नहीं भाया। इसलिये न केवल अंधभक्तो ने बल्कि साम्प्रदायिक विद्वेष के बल पर अपनी नैय्या पार करने की इच्छा पाले कई पराजित उम्मीदवारों ने भी मतदाताओं को ही गरियाना शुरू कर दिया।

# हाथरस हादसे में मौतों की जवाबदेही तय हो

एक डरावनी एवं संवेदनहीन हकीकत है कि हम ऐसे धर्म एवं धार्मिकता से जुड़े पिछले हादसों से कोई सबक नहीं सीखते। हाल के दिनों में भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में भगदड़ में लोगों के मरने के मामले लगातार बढ़े हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि भीड़ के बीच होने वाले हादसों को कैसे रोका जाए?

उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग के समापन के बाद मची भगदड़ में एक सौ इक्कीस लोगों के मरने एवं सैकड़ों लोगों के घायल होने की हृदयविदारक, दुःखद एवं दर्दनाक घटना ने पूरे देश को विचलित किया है। ऐसी घटनाएं न केवल प्रशासन की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी को उजागर कर रही है बल्कि धर्म के नाम पर पनप रहे आडम्बर, अंधविश्वास एवं पाखण्ड को भी उजागर कर रही है। ऐसी त्रासदियां एवं दिल को दहलाने देने वाली घटनाओं से जुड़े पाखण्डी बाबाओं की कारगुजारियों से हिन्दू धर्म भी बदनाम हो रहा है, जबकि सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले बाबा को हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह हादसा अनेक सवालों को खड़ा करता है, बड़ा सवाल है कि ऐसे बड़े आयोजन में सुरक्षा उपायों की अनदेखी क्यों होती है? सवाल उठता है कि इतना बड़ा आयोजन बिना पुख्ता इंतजाम के किसकी अनुमति से किया जा रहा था? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया? क्या इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस-प्रशासन का नहीं होता? क्या आयोजन-स्थल पर निकास द्वार, पानी, हवा, वैकल्पित चिकित्सा एवं चिकित्सक, गर्मी से बचने के पुख्ता इंजताम जरूरी नहीं थे? जवाबदेही तय हो भगदड़ में गयी जानों की। जाहिर है मौतों के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही घटना पर लीपापोती की कोशिश भी जमकर होगी, राजनीतिक दल एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर राजनीति भी करेंगे। यह तय है कि ऐसे बाबाओं की दुकान बिना राजनेताओं के वरदहस्त के चलनी संभव नहीं है। हाथरस के सिकंदराराऊ के निकट फुलरई के एक खेत में कथित हरि बाबा के एक दिवसीय सत्संग के दौरान यह हादसा हुआ। इस बाबा से जुड़ी बातें विसंगतियों से भरी है। सफेद कोट-पेंट, टाई पहनने वाला यह बाबा कोई पंडित नही है न साधु संत है, यह जूता पहनकर प्रवचन देता था। इस बाबा को कितने वेद पुराण का ज्ञान है? यह किस परंपरा से है? इसके गुरु कौन हैं? ऐसे अनेक प्रश्न है जो बाबा को शक एवं संदेह के घेरे में लेते हैं। इन्हें हिन्दू बाबा कैसे कहा जा सकता है? हिंदू धर्म में ऐसा कहां होता है? यह बाबा पहले पुलिस सेवा में थे और जिनका मैनपुरी में भव्य एवं महलनुमा आश्रम है। घटना के बाद बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। भारत में भोली-भाली जनता को ठगने एवं गुमराह करने वाले ऐसे पाखण्डी बाबाओं की बाढ़ आई हुई है। इस तरह की घटनाएं केवल जनहानि का कारण ही नहीं बनतीं, बल्कि देश एवं धर्म की बदनामी भी कराती हैं। इन घटनाओं पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाए राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी।

हाथरस की घटना कितनी अधिक गंभीर एवं चिन्ताजनक हैं, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने संबोधन के बीच इस हादसे की जानकारी दी एवं शोक-संवेदना व्यक्त की। दुनिया भर में इस घटना को लेकर दुःख जताया जा रहा है। यह तय है कि हाथरस में इतनी अधिक संख्या में लोगों के मारे जाने पर शोक संवेदनाओं का तांता लगेगा, लेकिन क्या ऐसे हादसों को नियंत्रित करने वाले ऐसे कोई उपाय भी सुनिश्चित कर सकेंगे, जिससे भविष्य में देश को शर्मिंदा करने वाली ऐसी घटना न हो सके? प्रश्न यह भी है कि आखिर धार्मिक आयोजनों में धर्म-कर्म का उपदेश देने वाले लोगों को संयम और अनुशासन की सीख क्यों नहीं दे पाते? कब तक ऐसे आयोजन धन कमाने के माध्यम बनते रहेंगे, जब जब धर्म का ऐसे पाखण्ड एवं पाखण्डियों से गठबंधन हुआ है, तब तक धर्म अपने विशुद्ध स्थान से खिसका है। यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि कई बार ऐसे आयोजनों में भगदड़ का कारण लोगों का असंयमित व्यवहार भी बनता है। ऐसा लगता है कि अपने देश में धार्मिक-सामाजिक आयोजनों में कोई इसकी परवाह नहीं करता कि यदि भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था फैल गई तो उसे कैसे संभाला जाएगा? क्या इसलिए कि प्रायः मारे जाने वाले लोग निर्धन एवं गरीब वर्ग के होते हैं?

एक डरावनी एवं संवेदनहीन हकीकत है कि हम ऐसे धर्म एवं धार्मिकता से जुड़े पिछले हादसों से कोई सबक नहीं सीखते। हाल के दिनों में भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में भगदड़ में लोगों के मरने के मामले लगातार बढ़े हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि भीड़ के बीच होने वाले हादसों को कैसे रोका जाए। दो साल पहले माता वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ में बारह श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अप्रैल 23 में बनारस की भगदड़ में 24 लोग मरे थे। खाटू श्याम में भी भीड़ में दब कर 4 लोगों की मौत हुई। इंदौर में पिछले साल रामनवमी के दिन बावड़ी की छत गिरने से पैंतीस लोग मर गये थे। इसी तरह 2016 में केरल के कोल्लम के एक मंदिर में आग लगने से 108 लोगों की मौत हुई और दौ से अधिक घायल हुए थे। पंजाब के अमृतसर में दशहरे के मौके पर रावण दहन देख रहे साठ लोगों के ट्रेन से कुचलकर मरने की घटना को नहीं भूले हैं। देश में भीड़ की भगदड़ से होने वाले 70 फीसदी हादसे धार्मिक आयोजनों के दौरान ही होते हैं। हाल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल से जुड़ा हादसा मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का में हुआ, जहां हज यात्रियों पर गर्मी का सितम इस कदर कहर बना कि 900 से ज्यादा मौतें हुई, जिनमें 90 भारतीय ने भी जाने गंवाई। विडम्बना है कि इन बड़े-बड़े हादसों से न तो जनता कुछ सीख लेती और न ही प्रशासन। यह हैरानी की बात है कि किसी ने यह देखने-समझने की कोई कोशिश नहीं की कि भारी भीड़ को संभालने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इस आयोजन की अनुमति देने वाले अधिकारियों ने भी कागजी खानापूर्त्ति करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी ने इस पर अवश्य ध्यान दिया होता कि आयोजन स्थल के पास का गड्ढा लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। जैसे-जैसे जीवन में धर्म का पाखण्ड फैलता जा रहा है, सुरक्षा उतनी ही कम हो रही है, जैसे-जैसे प्रशासनिक सर्तकता की बात सुनाई देती है, वैसे-वैसे प्रशासनिक कोताही के सबूत सामने आते हैं, ऐसे आयोजनों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हर बड़ी दुर्घटना कुछ शोर-शराबें के बाद एक और नई दुर्घटना की बाट जोहने लगती है। सरकार और सरकारी विभाग जितनी तत्परता मुआवजा देने में और जांच समिति बनाने में दिखाते हैं, अगर सुरक्षा प्रबंधों में इतनी तत्परता दिखाएं तो ऐसे जघन्य हादसों की संख्या घट सकती है। बहरहाल आने वाले दिनों में जांच के बाद किसी के सिर पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ा जाएगा। मगर इन मौतों का कसूरवार कौन है? जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी कमी कैसे पूरी होगी? कहा जा रहा है कि यह एक निजी कार्यक्रम था, कानून व्यवस्था के लिये प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन आयोजन स्थल पर भीतरी व्यवस्था आयोजकों के द्वारा की जानी थी। अब बड़े अधिकारियों का घटना स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके तीन मंत्री पहले से वहां पहुंचे हुए है। इस एवं इससे जुड़ी कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि आमतौर पर यही देखने में आता है कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई के नाम पर कुछ अधिक नहीं होता। इसी कारण रह-रहकर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी जान गंवाते हैं। इसके बावजूद कोई सबक सीखने को तैयार नहीं दिखता है। धार्मिक आयोजनों में अव्यवस्था और अनदेखी के चलते लोगों की जान जाने के सिलसिले पर इसलिए विराम नहीं लग पा रहा है, क्यों-कि दोषी लोगों के खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती, जो नजीर बन सके।

## प्लास्टिक के बैग का विकल्प पर्यावरण के अनुकूल हो

प्लास्टिक की थैलियों से होने वाले नुकसान से सभी वाकिफ हैं। सब जानते हैं कि ये जल्दी नष्ट नहीं होतीं, जमीन के अंदर वर्षों तक दबी रहती हैं, जलने पर पर्यावरण को दूषित करती हैं और इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। फिरभी यदि इनका व्यापक इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई न कोई वजह जरूर होगी? दिक्कत यह है कि हम उन कारणों को नहीं समझना चाहते और सिर्फ डंडे के बल पर प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं। यह संही रणनीति नहीं है। दरअसल, प्लास्टिक की थेलियों का कोई ठोस विकल्प अब तक हमारे सामने नहीं आ सका है। प्लास्टिक के बैग ने

बाजार से सामान लाना आसान बना दिया है। अब कोई चिंता नहीं रहती कि घर से निकलते वक्त हाथ में कोई बैग है अथवा नहीं। इसी तरह, राह चलते यदि कोई सामान पसंद आ जाए तो उसे ढूंढने के लिए प्लास्टिक बैग काफी सुगम होता है। ऐसे में लोगों से यह उम्मीद करना गलत होगा कि वह अपनी सुगमता को छोड़कर फिर से मुश्किल के दिनों की ओर लौट जाएं। बेहतर होगा कि सरकार प्लास्टिक बैग का ऐसा विकल्प प्रस्तुत करें जो पर्यावरण के अनुकूल भी और लोगों की मुश्किलें भी ना पढ़ाई अच्छी बात है कि अब कई स्टोर ऐसी प्लास्टिक थैलियां का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनका चरण संभव है और जो पर्यावरण के अनुकूल भी बताई जाती हैं। बहरहाल, कई जगहों पर खेल तार और अन्य बड़े पत्तों का इस्तेमाल करके फूड पैकेजिंग तैयार की जाती है। एसे ओं प्लास्टिक थैलियां का अच्छा विकल्प बनाया जा सकता है जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में होता है। अगर बड़े पत्तों पैकेट तैयार करने के उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू किया जाए तो खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग प्लास्टिक थैलियां से करने के अनिवार्यता समाप्त हो सकती है। मगर इसके लिए जरूरी है इन उद्योगों को बेहतर माहौल मिले और पर्याप्त पूंजी भी। पिछले दिनों या खबर भी प्रकाशित की गई थी की घास से थालिया बनाने का काम हो रहा है। अगर यह योजना सरकार हुई तो देश को काफी लाभ हो सकता है हां इसके लिए जरूरी है कि इन थैलियां की कीमतें प्लास्टिक बैग के आसपास हो या फिर उस काम तभी दुकानदार भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे ऐसा इसलिए किया जाना जरूरी है कि कागज की थैलियां अधिक लागत मूल्य के कारण चलन से बाहर हो गई हैं।

## एक नजर ऐसे ही 6 दर्दनाक हादसों पर जिसने देश को झकझोर कर रख दिया

**नई दिल्ली।** उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। सिकन्दराराऊ के थानाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि इस थाना क्षेत्र के फुलराई गांव में भोलेबाबा के सत्संग के दौरान यह भगदड़ मच गयी जिसमें 116 लोगों की मौत हो गई है तथा अनेक अन्य घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस में हुए हादसे का संज्ञान लिया( उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। यह पहली बार नहीं है कि देश में ऐसा हादसा हुआ है। मंदिरों में भीड़ या अन्य वजहों से पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक नजर ऐसे ही 6 दर्दनाक हादसों पर जिसने देश को झकझोर कर रख दिया।

3 फरवरी 1954 को जब पहली बार आजाद भारत में कुंभ मेले का आयोजन किया गया, तो यह एक दर्दनाक हादसा में बदल गया था। मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना में 800 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 2000 से अधिक घायल हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स की मानें, तो इस हादसे में 300 से अधिक मौतें कुचले जाने से हुई, जबकि 200 से अधिक लापता हो गए थे।

महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित मंधारदेवी मंदिर में मची भगदड़ को भी नहीं भुलाया जा सकता है। 25 जनवरी 2005 को मंदिर में हुए हादसे में करीब 350 लोगों की मौत हो गई थी। मंदिर में भगदड़ उस वक्त मची, जबकि श्रद्धालु नारियल तोड़ने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और उसी दौरान फिसलन की वजह से कुछ लोग सीढ़ियों से गिर गए, जिसके बाद वहां अचानक से हालात खराब हो गए।

हिमाचल प्रदेश का नैना देवी मंदिर भी एक हादसे का शिकार बना था। यहां माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटती है। 3 अगस्त 2008 को माता के दर्शन की लालसा में हजारों की तादाद में लोग नैना देवी मंदिर पहुंचे। इसी दौरान बारिश की वजह से मंदिर में लैंडस्लाइड हुआ और भगदड़ मचने से करीब 150 भक्तों की मौत हो गई।

ऐसा ही एक हादसा **30 सितंबर 2008** को राजस्थान के जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर में हुआ था, जहां शारदीय नवरात्र के दौरान बम विस्फोट की अफवाह फैली और इसके तुरंत बाद वहां अफरातफरी मच गई. नतीजा यह हुआ कि भगदड़ में करीब 250 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए थे।

**मार्च, 2010** उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कृपालुजी महाराज के आश्रम का गेट गिरने से मची भगदड़ में 63 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए. मरने वालों में 37 बच्चे और 26 महिलाएं थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने बताया था कि मौतें आश्रम का गेट गिरने से मची भगदड़ से हुई थीं। **7 मार्च 2023:** मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर का स्लैब टूट गया थाङ्घ स्लैब टूटने से मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई और 36 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के समय बावड़ी पर जो स्लैब डाला गया था, उस पर करीब 60 श्रद्धालु मौजूद थे।

## गंडक उफान पर, सवा लाख क्यूसेक डिस्चार्ज

**पडरौना, कुशीनगर (जीकेबी)।** नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र पोखरा में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। बुधवार की सुबह वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से 1 लाख 24 हजार क्यूसेक पानी नदी में डिस्चार्ज कर दिया गया। इससे गंडक उफान पर आ गई। खड्डा के भैंसहा गेज पर जलस्तर बढ़ने के बाद नदी 24 सेमी ऊपर बहने लगी। जलस्तर में हुई वृद्धि को देखते हुए खड्डा से लेकर तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के तटबंधों के किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई।

हालांकि, दोपहर बाद डिस्चार्ज में कमी दर्ज की गई। शाम पांच बजे 1 लाख 19 हजार क्यूसेक डिस्चार्ज रहा। डिस्चार्ज में कमी के बाद नदी का जलस्तर भी कम होने लगा और शाम के वक्त नदी चेतावनी बिंदु से नीचे आ गई। दूसरी तरफ, बढ़ते-घटते जलस्तर से कई जगह तटबंधों पर नदी का दबाव भी बढ़ गया है।

नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र पोखरा में हो रही बारिश के कारण बुधवार को बड़ी गंडक नदी उफान पर आ गई। वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से तीन बार पानी नदी में डिस्चार्ज किया गया। 1 लाख 24 हजार क्यूसेक पानी सुबह डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी। खड्डा के भैंसहा गेज पर नदी चेतावनी बिंदु 95 मीटर के सापेक्ष 95.24 मीटर यानि 24 सेमी ऊपर बहने लगी। यह देख बाढ़ खंड विभाग के जिम्मेदार सतर्क हो गए।

कंट्रोल रुम से भी डिस्चार्ज के पल-पल की जानकारी लेने में अधिकारी जुट गए। दोपहर बाद डिस्चार्ज में कमी होने लगी। शाम पांच बजे के बाद डिस्चार्ज में कमी होने से नदी चेतावनी बिंदु से नीचे आ गई। जलस्तर के घटने-बढ़ने से जिले के तटबंधों पर कुछ जगहों पर नदी का दबाव भी बढ़ गया। छितौनी बांध के संवेदनशील जगहों पर नदी का दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा अमवा खास तटबंध के किमी 8.6 लक्ष्मीपुर के सामने नदी बांध से सटकर बहने लगी। हालांकि, यहां बोल्डर पिचिंग का कार्य कराया गया है, जिससे इतने जलस्तर पर नदी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती।

वहीं, तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के नरवाजोत, अहिरौलीदान के कचहरी टोला, डीह टोला समेत अन्य टोले के लोग जलस्तर के उतार-चढ़ाव पर नजर रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि मानसून के दस्तक देने

के बाद से ही उनकी परेशानी बढ़ जाती है। परियोजनाओं के तहत कार्य तो कराए गए हैं, लेकिन अत्यधिक पानी डिस्चार्ज किए जाने के कारण अब भी कई टोलों में पानी भर जाता है।

### खड्डा के महदेवा गांव पर मंडराया खतरा

बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से लगातार चौथे साल भी खड्डा तहसील के महदेवा गांव पर खतरा मंडरा रहा है। गांव से महज 40 मीटर की दूरी पर नदी बह रही है। पिछले साल परक्यूपाइन लगाकर नदी की धारा मोड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन विभाग की यह कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। लिहाजा, इस साल भी मानसून की दस्तक के बाद महदेवा गांव पर संकट बढ़ गया है। इसके अलावा रेताक्षेत्र के मरिचहवा, बकुलादह, शिवपुर, नारायणपुर और हरिहरपुर गांव के लोग जलस्तर बढ़ने के बाद चिंतित हैं। इन गांवों के लोगों का कहना है कि नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद वह दिन तो गुजार लेते हैं, लेकिन रात के वक्त वह बाढ़ की आशंका में चैन से सो भी नहीं पाते।

## तोता-मैना व गौरैया की तरह ललमुनिया भी प्रतिबंधित

हरैया के वन रेंजर शारदानंद तिवारी ने बताया कि 505 ललमुनिया चिड़ियों को संत रविदास पार्क में पिजड़ों से आजाद कर दिया गया है। इन्हें चेस्टनेक मुनिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भी लोग तोता-मैना व गौरैया की तरह पालते हैं। जबकि अब इनका पालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इन्हें या तो खुले तौर पर छोड़ दिया जाए या फिर वन विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है।

## ललमुनिया चिड़ियों की भारी खेप फॉरेस्ट टीम ने किया

**बस्ती (जीकेबी)।** प्रतिबंधित ललमुनिया चिड़ियों की भारी खेप फॉरेस्ट टीम ने बरामद किया है। कुल 505 चिड़ियों के समूह को फॉरेस्ट टीम ने कोर्ट के आदेश पर शहर से सटे वन विहार पार्क में छोड़ दिया है। न्यायालय ने पक्षियों को ले जा रहे तस्कर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लखनऊ स्थित वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को सूचना मिली कि बस्ती जिले के श्रीरामजानकी मार्ग स्थित छावनी बाजार के करीब रानी बगिया के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित ललमुनिया चिड़ियों को पिजड़ों में लेकर कहीं जा रहा है। डीएफओ जेपी सिंह ने फॉरेस्ट के एसटीएफ टीम को टास्क सौंप दिया। हरैया के वन रेंजर शारदानंद तिवारी व सचल दल प्रभारी राजकुमार की टीम ने घेराबंदी कर 505 चिड़ियों के पिजरों को अपने कब्जे में ले लिया और तस्करी के आरोपी शहजाद निवासी सहदेउरी-खेतासराय, जिला जौनपुर को गिरफ्तार कर लिया।

टीम ने उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से शहजाद को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और चिड़ियों को शहर से सटे संतरविदास पार्क में छोड़ने का आदेश दे दिया गया।

## जल भराव से स्थानीय लोग भयभीत

**आनन्दनगर (जीकेबी)।** गोरखपुर सोनौली राजमार्ग पर स्थित भैया फरेंदा चौराहे के दोनों तरफ जलभराव हो गया है, जिसके कारण स्थानीय लोग भयभीत हैं। बारिश के मौसम में व्यापारी किसी अनहोनी को लेकर चिंतित हैं। कार्यदायी संस्था की लापरवाही भी सामने आ रही है। मकानों की तोड़फोड़ के बाद भवनों की स्थित जर्जर हो गई है। भैया फरेंदा कस्बे में शुक्रवार को दो मंजिला पक्का मकान भरभराकर गिर गया। इसके बाद से लोगों में मकान को लेकर दहशत बना हुआ है। राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसको लेकर सड़क के दोनों तरफ खोदाई भी कर दी गई है। सड़क के किनारे खोदाई के बाद हुई बरसात में दोनों तरफ जलभराव हो गया है। सड़क का पानी लोगों के घरों की नींव में जा रहा है। इसको लेकर मकान में रहने वाले लोगों की रातें दहशत में कट रही हैं। कार्यदायी संस्था पीएनसी कार्य में लापरवाही बरत रही है। धीमी गति से काम होने के कारण काफी समय लग जाएगा। नतीजा लोगों के मकान भी ढह सकते हैं। सड़क के किनारे के मकान जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। जलजमाव के कारण व्यापारियों का धंधा भी चौपट हो गया है। कार्यदायी संस्था की ओर से सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण भी कराया जा रहा है बरसात के दिनों में काम ठप हो गया है। बिजली के खंभे भी नई जमीन में लगने के कारण बारिश में गिर रहे हैं। नतीजा किसी के मकान पर तार गिरा तो बड़ी घटना हो सकती है।

## आए दिन छूटती हैं बसें, यात्री परेशान

**नौतनवा(जीकेबी)।** गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनौली डिपो से चलने वाली रोडवेज बसें शहर से न होकर बाईपास से सीधे आवागमन कर रही हैं। इससे यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को आए-दिन बसें बाईपास पर छोड़ देती हैं। उन्हें कस्बे के अंदर पैदल चलकर आना पड़ता है या फिर वाहनों के लिए भटकना पड़ता है। गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली रोडवेज बस इस समय कुछ नौतनवा कस्बा, अधिकतर बसें बाईपास से होकर जा रही हैं। जिससे यात्रियों को काफी समस्या हो रही।

गोरखपुर की तरफ से आने वाली बसें जब छपवा तिराहे से बाईपास होकर सोनौली डिपो के लिए जाती हैं तो नौतनवा कस्बा में या गांधी चौक पर उतरने वाले यात्रियों को टेंपों से जाना पड़ता है। रात में साधन न मिलने पर लोगों को पैदल जाना पड़ता है। बाईपास पर अंधेरा कुछ रोडवेज की बसें को छोड़कर बाकी डिपो की बसें अधिकतर बाईपास से ही होकर आ-जा रही हैं। जिससे कस्बे के अंदर बस स्टैंड और अन्य ठहराव स्थलों पर यात्री घंटो बसों के इंतजार में परेशान हो रहे हैं। हर रोज बड़ी संख्या में यात्री कामकाज के लिए या रोजगार के बडे. शहरों को जाते हैं। कस्बे से न होकर बसें बाईपास से सीधे आवागमन कर रही हैं। यात्रियों को आए-दिन बसें बाईपास पर छोड़ देती हैं। रात के समय में बाईपास के दोनों छोर पर अंधेरा रहता है। ऐसे में वहां उतरने के बाद यात्रियों को कस्बे के अंदर तक आने में अपने साथ अनहोनी का डर भी सताता है। यात्री कौशिल्या, गुड़िया, मीरा देवी, रीमा राय, रोहित, रामाज्ञा यादव, रामरतन, सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र आदि ने बताया कि रोडवेज बाईपास पर छोड़ देने से कस्बे में पैदल चलकर आना पड़ा। सोनौली डिपो के एआरएम एनके चौधरी ने बताया कि बसें शहर से होकर जाती है। अगर ऐसी बात है तो समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

## यहां दबंगों का दबदबा रहता है....

बस्ती( जीकेबी )। शहर एवं आसपास के प्रमुख चौराहों पर अवैध टैक्सी स्टैंड की भरमार है। अलग-अलग रूटों के लिए मनमाने ढंग से जगह निर्धारित कर लिए गए हैं। यहां दबंगों का दबदबा रहता है। बगैर उनकी मर्जी के टैक्सी वाहन में कोई सवारी बैठा नहीं सकता। अवैध रूप से प्रति चक्कर शुल्क जमा करने के बाद ही नंबर मिल रहा है। यह खेल लंबे समय से चल रहा है। मगर, प्रशासन या नगर पालिका इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा।

शहर से लेकर आसपास के चौराहों पर अवैध टैक्सी स्टैंड बन गए हैं। जहां सवारी बैठाने को लेकर चालकों में अक्सर खींचतान और मारपीट होते देखा जा सकता है। स्थानीय दबंगों का यहां सिक्का चल रहा है। कई स्टैंड तो पुलिस की नाक के नीचे चल रहे हैं। मगर, पुलिस नजर अंदाज कर देती है। बड़ेबन, फुटहिया, मनौरी चौराहा, अस्पताल चौराहा, रेलवे स्टेशन के बरदहिया मोड़, महुली रोड इनमें प्रमुख हैं। असल में

*अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित होने की जानकारी नहीं है। यदि शहर में टैक्सी स्टैंड के नाम पर वसूली हो रही है तो जांच कराई जाएगी। ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।*

**-सत्येंद्र कुमार सिंह,**
प्रभारी ईओ/एसडीएम

उधर से गुजरने वाले टैक्सी वाहन अगर चौराहे पर खड़े होकर सवारी बैठाते हैं तो दबंग ऑटो चालक या अनधिकृत स्टैंड के संचालक मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। बड़ेवन चौराहे पर लखनऊ रूट की बसों से अनधिकृत स्टैंड के नाम पर प्रतिदिन अच्छी-खासी वसूली की जा रही है।

चालकों का आरोप है कि गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर और लखनऊ की बसों से एक बार में 200 रुपये तक की वसूली हो रही है। मनौरी चौराहे पर भी अवैध ऑटो-टैक्सी स्टैंड हैं। यहां दबंगों की मर्जी के बगैर वाहनों में कोई सवारी नहीं बैठा सकता। पिछले साल एक ऑटो चालक से सवारी बैठाने के चक्कर में मारपीट हो गई थी। पुरानी बस्ती थाने में केस तक दर्ज हुआ। बावजूद इसके यहां दबंगों का कहर खत्म नहीं हुआ।

### फुटहिया पर देना पड़ रहा स्टैंड शुल्क

कचहरी चौराहा से कलवारी-टांडा के लिए सवारी भरने पर ऑटो एवं जीप चालकों को अवैध रूप से स्टैंड शुल्क देना पड़ रहा है। ऐसा न करने पर दबंग वाहन चालकों को सवारी नहीं भरने दे रहे हैं। यदि चोरी-छिपे यहां से सवारी लेकर निकल भी लिए तो आगे फुटहिया चौराहे पर पहुंचते ही उन्हें रोक लिया जाता है। यहां उनसे स्टैंड शुल्क के नाम पर अवैध रूप से वसूली की जाती है। चालक हरीराम, रंजीत, राम प्रताप ने बताया कि कचहरी पर अधिकृत स्टैंड नहीं है। फिर भी दबंग लोग उनसे प्रति चक्कर 50 रुपये शुल्क वसूल रहे हैं। न देने पर सवारी नहीं भरने देते। ऊपर से मारपीट भी करते हैं।

### अस्पताल चौराहा पर भी अवैध स्टैंड

अस्पताल चौराहा से जामडीह तक अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हो रहा है। ओपेक चिकित्सालय कैली, सोनूपार, महसो, बनकटी और महुली तक की सवारियां यहां बैठाई जा रही है।

टैक्सी चालकों से प्रति चक्कर शुल्क जमाकर नंबर दिया जाता है। इस दौरान यदि कोई टैक्सी चालक बिना शुल्क जमा किए सवारी बैठाया तो उसकी खैर नहीं। अवैध स्टैंड के संचालक उस पर टूट पड़ते हैं। मारपीट तक की नौबत आ जा रही है।

# सामाजिक आन्दोलनों में भाग नहीं लेते आज के लेखक

स्वामी जी की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी जनसभा में महात्मा गांधी से अधिक लोग आते थे और उसे जमाने में पटना एक-एक लाख की भीड़ स्वामी जी के नाम पर जमा हो जाती थी स्वामी जी का संबंध अपने समय के बड़े नेताओं से तो थे ही, जका घरनिष्ठ संबंध हिंदी के कई बड़े लेखकों से भी था और उन लोगों ने उनके किसान आंदोलन में खुलकर भाग लिया था। अब तक हम लोग यही जानते रहे थे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन में महा पंडित राहुल साकृत्यायन रामवृक्ष बेनीपुरी, दिनकर, बाबा नागार्जुन जैसे लेखक शामिल थे लेकिन पिछले दिनों हिंदी साहित्य की दुनिया में एक नए तथ्य का पता चला है कि आचार्य शिवपूजन सहाय भी उस आदोलन में पूरी तरह शामिल थे। शिवपूजन जी की छवि एक संत साहित्यकार की रही है जिसने निर्विकार और निस्पृह भाव से साहित्य की सेवा करते हुए अपना जीवन होम कर दियां लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें लोग आज भी नहीं जानते इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि शिवदूजन सहाय बड़े ही आत्म गोपन व्यक्ति थे और हमेशा पर्दे के पीछे रहे। शिवपूजन सहाय ने स्वामी जी को 1939 में पत्र लिखे थे। संभव है शिवपूजन सहाय ने स्वामी जी को और भी पत्र लिखे हो क्यंकि इन पत्रो में एक अगस्त 1939 के एक पत्र का भी जिक्र है और न पत्रों से पता चलता है कि स्वामी जी के साथ शिवपूजन सहाय का सवाद काफ पुराना और लंबा था। ये पत्र शाहाबाद जिला किसान सभा के लेटर पैड पर लिएहेते गए हैं। जाहिर है कि शिवपूजन सहाय भी इस किसान सभा के कर्ता धर्ता रहे होंगे तभी उन्होंने इस लेटर हेड पर स्वामी जी को यह पत्र लिखे थे। अगर इन सारे प्रसंगों को देखा जाए तो पता चलता है कि 1930 के दशक में हिंदी के लेखकों ने स्वामी जी के किसान आंदोलन में न केवल भाग लिया बल्कि उनकी रचनाओं में भी किसान जीवन सामने आया। प्रेमचन्द के किसान संबंधी लेखन के पीछे भी स्वामी जी के किसान आंदोलन का हाथ रहा होगा। बेनीपूरी जी ने विशाल भारत में किसानों की समस्यायों पर लेख भी लिखे थे। राहुलजी पर जब लाठी से हमला किया गया तो बेनीपरी जी ने उसके विरोध में लिखा भी था राहल जी और स्वामी जी हजारी बाग जैल में साथ साथ बन्द्र थे वही उन्होंने मेरी जीवन यात्रा लिखी तो स्वामी जी ने मेरा जीवन संघर्ष लिखा। श्री कैलाशचन्द्र झा के अनुसार बाबा नागार्जुन ने भी स्वामी जी के किसान आंदोलन में भाग लिया था। अवधेश प्रधान ने स्वामीजी की आत्मकथा श्मेरा जीवन संघर्ष के साथ-साथ उनकी एक और पुस्तकश्महारुद्र का महा तांडव' को भी इसके साथ शामिल किया है क्योंकि 'मेरा जीवन संघर्ष' में केवल 1940 तक की घटना का जिक्र है जबकि दूसरी पुस्तक 1948 में लिखी गयी और उसमें उसके बाद की घटनाओं का जिक्र है स्वामीजी ने मेरा जीवन संघर्ष समेत 8 किताबें हजारीबाग जेल में लिखी थी जब वे 1940 से 42 तक उसमें रहे। हिंदी की दनिया में यह सवाल अक्सर उठता है कि उसके बड़े लेखक सामाजिक आंदोलनों में भाग नहीं लेते। आज के लेखक को किसानों मजदूरों से कोई मतलब नहीं रह गया है भले ही भी वे प्रतिबद्ध और प्रगतिशील होने का दावा क्यों न करते हों लेकिन एक जमाना था जब हिंदी के बड़े लेखकों ने किसान आदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रसिद्ध आलोचक एवम विद्वान अवधेश प्रधान द्वारा हाल ही में संपादित स्वामी जी की आत्मकथा 'मेरा जीवन संघर्ष' आयी है जिसको पढ़ने से यह पता चलता है कि महा पंडित राहल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोगों ने स्वामी सहजानन्द सरस्वती के किसान आंदोलन का न केवल समर्थन किया वल्कि उसमें भाग भी लिया था और कई लोगों ने उन पर कविताएं भी लिखी थीं। स्वामी जी उस जमाने मे इतने लोकप्रिय हो गए कि उन पर लोकगीत भी लिखे गए। स्वामी जी की आत्मकथा 'मेरा जीवन संघर्ष के अंग्रेजी अनुवादक एवं भारतमें स्वामी जी नेतृत्व में हुए किसान आंदोलन के अमरीकी आध्येयता वाल्टर हाउजर के सहयोगी कैलाश चन्द्र झा ने स्थामी जी के कई दुर्लभ पत्रों को पहली बार हिंदी साहित्य के सामने उजागर किया है जिसमें तीन महत्वपूर्ण पत्र आचार्य शिवपूजन सहाय के भी हैं जिससे पता चलता है कि स्वामी जी के किसान आंदोलन में शिवपूजन जी भी गहरे रूप से जुड़े हुए थे और वह तो जेल जाते-जाते बच गए थे हालांकि अवधेश प्रधान द्वारा संपादित इस पुस्तक में सहाय के पत्रों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये पत्र अभी हाल ही में श्री झा को मिले हैं जब श्री झा ने वाल्टर हाउजर के निधन के बाद उनकी सारी सामग्री को अमेरिका से लाया।

शिवपूजन जी के इन ऐतिहासिक पत्रों को स्त्री लेखा पत्रिका ने प्रकाशित किया है। श्री झा को जे पी, राहुल जी और नागार्जुन के स्वामी जी के नाम लिखे पत्र भी मिले हैं। श्री झा और हाउजर ने मिलकर स्वामी जी की आत्मकथा का अनुवाद किया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती केवल राजनीतिक आजादी के समर्थक नहीं थे बल्कि जमीनदारों से भी देशवासियों को मुक्त कराना चाहते थे किसानों का शोषण केवल अंग्रेज ही नहीं यहां के जमींदार भी करते थे। इसलिए स्वामी जी ने 1936 में लखनऊ के में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। लेकिन उनकी आत्मकथा उनके जीते जी नहीं छपी। उसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। श्री कैलाश चन्द्र झा को हाल ही में स्वामी जी और किताब महल के बीच पत्रव्यहार में से एक पत्र मिला है जिसमें इस पुस्तक के न छपने की कहानी छिपी है।

# आखिर क्यों चुप्पी साध गई पक्षियों की चहचाहट?

पक्षियों को पर्यावरण की स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक माना जाता है। क्योंकि वे आवास परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं और पक्षी पारिस्थितिकीविद् के पसंदीदा उपकरण हैं। पक्षियों की आबादी में परिवर्तन अक्सर पर्यावरणीय समस्याओं का पहला संकेत होता है। चाहे कृषि उत्पादन, वन्य जीवन, पानी या पर्यटन के लिए पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन किया जाए, सफलता को पक्षियों के स्वास्थ्य से मापा जा सकता है। पक्षियों की संख्या में गिरावट हमें बताती है कि हम आवास विखंडन और विनाश, प्रदूषण और कीटनाशकों, प्रचलित प्रजातियों और कई अन्य प्रभावों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

**बदल रहे हर रोज ही, हैं मौसम के रूप ।**
**सर्दी के मौसम हुई, गर्मी जैसी धूप ।।**
**सूनी बगिया देखकर, ह्यतितली है खामोशह्ल ।**
**जुगनूं की बारात से, गायब है अब जोश ।।**

हाल ही की एक रिपोर्ट, 'स्टेट ऑफ द वल्ड्र्स बड्र्स' के अनुसार, दुनिया भर में मौजूदा पक्षी प्रजातियों में से लगभग 48% आबादी में गिरावट के दौर से गुजर रही है या होने का संदेह है। प्राकृतिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में पक्षियों का पारिस्थितिक महत्व है। पक्षी कीट और कृंतक नियंत्रण, पौधे परागण और बीज फैलाव प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों को ठोस लाभ होता है। कीट का प्रकोप सालाना करोड़ों डॉलर के कृषि और वन उत्पादों को नष्ट कर सकता है। पर्पल मार्टिंस लंबे समय से हानिकारक कीटनाशकों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लागत (आर्थिक लागत का उल्लेख नहीं) के बिना कीट कीटों की आबादी को काफी हद तक कम करने के एक प्रभावी साधन के रूप में जाना जाता है।

**आती है अब है कहाँ, कोयल की आवाज ।**
**बूढा पीपल सूखकर, ठूंठ खड़ा है आज ।।**
**जब से की बाजार ने, हरियाली से प्रीत ।**
**पंछी डूब दर्द में, फूटे गम के गीत ।।**

पक्षी प्राकृतिक प्रणालियों में कीड़ों की आबादी को कम करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्वी जंगलों में पक्षी 98% तक बुडवार्म खाते हैं और 40% तक सभी गैर-प्रकोप कीट प्रजातियों को खाते हैं। इन सेवाओं का मूल्य 5,000 डॉलर प्रति वर्ष प्रति वर्ग मील वन पर रखा गया है, संभावित रूप से पर्यावरण सेवाओं में अरबों डॉलर में अनुवाद किया जा सकता है। पक्षियों और जैव विविधता के नुकसान का सबसे बड़ा खतरा आवासों का विनाश और क्षरण है। पयार्वास के नुकसान में प्राकृतिक क्षेत्रों का विखंडन, विनाश और परिवर्तन शामिल है, जिन्हें पक्षियों को अपने वार्षिक या मौसमी चक्र को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

**फीके-फीके हो गए, जंगल के सब खेल ।**
**हरियाली को रौंदती, गुजरी जब से रेल ।।**
**नहीं रहे मुंडेर पर, तोते-कौवे-मोर ।**
**लिए मशीनी शोर है, होती अब तो भोर ।।**

1800 के दशक के बाद से अधिकांश पक्षी विलुप्त होने के लिए आक्रामक प्रजातियां जिम्मेदार हैं, जिनमें से अधिकांश समुद्री द्वीपों पर हुई हैं। उदाहरण के लिए, अकेले हवाई में, आक्रामक रोगजनकों और शिकारियों ने 71 पक्षी प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दिया है। कुछ पक्षियों का अवैध शिकार वाणिज्यिक और निर्वाह उद्देश्यों के लिए, भोजन के लिए, या उनके पंखों के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, कुछ प्रजातियों का अत्यधिक शिकार विलुप्त होने का प्रमुख कारण रहा है। स्थानीय स्तर पर निर्वाह के शिकार के परिणामस्वरूप शायद ही कभी प्रजातियों का विलोपन होता है। व्यावसायिक शिकार से किसी प्रजाति के मरने की संभावना अधिक होती है।

**अमृत चाह में कर रहे, हम कैसे उत्थान ।**
**जहर हवा में घोलते, हुई हवा तूफान ।।**
**बेचारे पंछी यहाँ, खेलें कैसे खेल ।**
**खड़े शिकारी पास में, ताने हुए गुलेल ।।**

जलवायु परिवर्तन से आवास के नुकसान और आक्रामक प्रजातियों के खतरों के साथ-साथ नई चुनौतियों का निर्माण करने का खतरा है, जिन्हें पक्षियों को दूर करना होगा। इसमें आवास वितरण में बदलाव और चरम खाद्य आपूर्ति के समय में बदलाव शामिल है जैसे कि पारंपरिक प्रवासन पैटर्न अब पक्षियों को नहीं रख सकते हैं जहां उन्हें सही समय पर होने की आवश्यकता होती है। अन्य मानव निर्मित संरचनाओं के साथ टकराव भी एक इनकी मौत का कारण है। उदाहरण के लिए, पावरलाइन पक्षियों के लिए एक खतरा पेश करती है, विशेष रूप से बड़े पंखों वाले, और हर साल 25 मिलियन पक्षियों की मौत का अनुमान है। संचार टावरों का अनुमान है कि हर साल 7 मिलियन पक्षियों की मौत हो जाती है और रात में प्रवास करने वाले पक्षियों के लिए एक विशेष खतरा पैदा होता है।

**वाहन दिन भर दिन बढ़े, खूब मचाये शोर ।**
**हवा विषैली हो गई, धुआं चारों ओर ।।**
**बिन हरियाली बढ़ रहा, अब धरती का ताप ।**
**जीव-जगत नित भोगता, कुदरत के संताप ।।**

कीटनाशक और अन्य विषाक्त पदार्थ के कारण यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस का अनुमान है कि हर साल लगभग 72 मिलियन पक्षी कीटनाशक विषाक्तता से मर जाते हैं। पक्षियों पर कीटनाशकों के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है: प्रदूषण और विषाक्त पदार्थ उप-घातक प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो सीधे पक्षियों को नहीं मारते हैं, लेकिन उनकी लंबी उम्र या प्रजनन दर को कम करते हैं। कीटनाशकों के अलावा, भारी धातुओं (जैसे सीसा) और प्लास्टिक कचरे सहित अन्य संदूषक भी पक्षियों के जीवन काल और प्रजनन सफलता को सीमित करते हैं। तेल और अन्य ईंधन रिसाव का पक्षियों, विशेष रूप से समुद्री पक्षियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तेल पक्षियों के पंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है है, जिससे पंख अपने जलरोधक गुणों को खो देता है और पक्षी की संवेदनशील त्वचा को अत्यधिक तापमान में झुलसा देता है।

**जीना दूभर है हुआ, फैले लाखों रोग ।**
**जब से हमने है किया, हरियाली का भोग ।।**
**शहरी होती जिंदगी, बदल रहा है गाँव ।**
**धरती बंजर हो गई, टिके मशीनी पाँव ।।**

दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों की रक्षा करें,महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पक्षी सर्वेक्षण करना,पक्षियों की रक्षा के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करें संरक्षण रणनीति में जनसंख्या बहुतायत और परिवर्तन का विश्वसनीय अनुमान लगाना शामिल है। अधिक कटाई वाले जंगली पक्षियों की मांग में कमी के लिए नए और अधिक प्रभावी समाधान बड़े पैमाने पर लागू किए गए। हरित ऊर्जा संक्रमणों की निगरानी करना जो अनुपयुक्त तरीके से लागू किए जाने पर **पक्षियों को प्रभावित कर सकते हैं।**

**रोज प्रदूषण अब हरे, धरती का परिधान ।**
**मौन खड़े सब देखते, मुँह ढाँके हैरान ।।**
**हरे पेड़ सब कट चले, पड़ता रोज अकाल ।**
**हरियाली का गाँव में, रखता कौन ख्याल ।।**

पक्षी पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अत्यधिक दृश्यमान और संवेदनशील संकेतक हैं, उनका नुकसान जैव विविधता के व्यापक नुकसान और मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरे का संकेत देता है। इस प्रकार, हमें तेजी से बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की गति को कम करने के लिए प्रकृति पर बढ़ते मानव पदचिह्न को कम करने के लिए सरकार, पर्यावरणविदों और नागरिकों के समन्वित कार्यों की आवश्यकता है।

**सच्चा मंदिर है वही, दिव्या वही प्रसाद ।**
**बँटते पौधे हों जहां, सँग थोड़ी हो खाद ।।**
**पेड़ जहां नमाज हो, दरख़्त जहां अजान ।**
**दरख्त से ही पीर सब, दरख्त से इंसान ।।**

- डॉ सत्यवान 'सौरभ',

## कब जिंदगी की शाम हो जाए

काम करो ऐसा कि आदमी अच्छा इंसान हो जाये
ज्यादा नहीं बस लोगों में इक पहचान हो जाये
किसी के काम आ जाओ करते रहो कुछ ऐसा
न जाने कब जिन्दगी की शाम हो जाये
पतझड़ में पता पेड़ से है टूट जाता
टूट गया जो फिर जुड़ नहीं पाता
नई कोंपलें आती है फिर टूट हैं जाती
यही सिलसिला जीवनपर्यंत चलता है जाता
फूल खिलता है खुशबू चमन में है फैलाता
जिंदगी लोगों की खुश्बू से है महकाता
पतझड़ के बाद तो है बसंत को ही आना
बसंत से तो प्रकृति में नवरस का संचार हो जाता
जीवन एक खेल है खेलना तो पड़ेगा
कोई हार जाएगा कोई जीत के लिए लड़ेगा
कितनी देर तक जलेगा जिन्दगी का दीपक
हमारे हाथ में नहीं यह तो ऊपरवाला ही तय करेगा

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

## समर्थन

विधवा शब्द कहना कठिन
उससे भी कठिन
अँधेरी रात में श्रृंगार का त्याग
श्रृंगारित रूप का विधवा में विलीन होना
जीवन की गाड़ी के पहिये में
एक का न होना चेहरे पर कोरी झूठी
मुस्कान होना
घर आँगन में पेड़ झड़ता सूखे पत्ते
ये भी साथ छोड़ते
जीवन चक्र की भाति
सुना था पहाड़ भी गिरते
स्त्री पर पहाड़ गिरना समझ आया
कुछ समय बाद पेड़ पर पुष्प हुए पल्लिव्त
जिन्हें बालों में लगाती थी कभी
वो बेचारे गिर कर कहरा रहे और मानो
कह रहे उन लोगो से जो
शुभ कामों में तुम्हे धकेलते पीछे
स्त्री का अधिकार न छीनो
बिन स्त्री के संसार अधूरा
हवा फूलों की सुगंध के साथ
मानों कर रही हो गिरे
पूष्प का समर्थने

संजय वर्मा 'दृष्टि'
125 बलिदानी भगत सिंह मार्ग
मनावर जिला -धार (म प्र)

# बाबाओं के मायाजाल में फंसती भीड़

पिछले कुछ दशकों से उभरने वाले किस्म-किस्म के बाबाओं ने राष्ट्र के मुख पर कालिख पोतने का का किया है। अपनी अनुयायी स्त्रियों के शारीरिक शोषण, हत्या-अपहरण से लेकर अन्य जघन्य अपराध करने वाले बाबाओं का प्रभाव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि आज जनता को तो छोड़िये, सदिच्छाओं वाले राजनेता, अभिनेता, अधिकारी, बुद्धिजीवी इत्यादि वर्ग भी उनसे घबराने लगा है। आखिर इन बाबाओं के महाजाल का समाजशास्त्र क्या है? इसी तरह सवाल यह भी है कि इनके पीछे जनता के भागने का क्या अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान है? आजकल विभिन्न सामाजिक वर्गों में अलग-अलग किस्म के अंधविश्वास प्रचलित हैं। इतने जागरूकता अभियानों के बावजूद आज भी आपको गांव-कस्बों में भूत-प्रेत के किस्से सुनने को मिल जाएंगे। वहीं हायर क्लास के अंधविश्वास अलग हैं। इस क्लास में भी असुरक्षा की भावना कम नहीं है। इस वर्ग के लोग यूं तो अत्याधुनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे एयरकंडिशंड आश्रमों वाले गुरुओं के यहां लाखों का चढावा चढाने से लेकर अपनी सफलता/असफलता की वजह लकी चार्म को मानने से भी गुरेज नहीं करते।

ऐसी मान्यताएं भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में पाई जाती हैं। सवाल यह उठता है कि समाज में अतार्किक विचारधारा वाले इतने अधिक लोग कहां से आ गए? जवाब है, वह परवरिश और माहौल जो हम अपने बच्चों को देते हैं। शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उतने प्रयास नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। संयुक्त परिवारों का टूटना और नई जीवन शैली का एकाकीपन, यांत्रिकता, तनाव आदि से पिछले रसायन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां हर व्यक्ति परेशान और बेचैन हो चला है। इन्हीं सामाजिक-मनोवैज्ञनिक स्थितियों के बीच लोग जाने-अनजाने ऐसे बाबाओं की ओर उन्मुख होने लगते हैं जो लोगों को हर दुःख-तनाव से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। लोगों में वहम पैदाकर फायदा उठाने की कला बाजार ने भी सीख ली है। यही वजह है कि बाजार के जन्म दिए हुए बहुत सारे त्योहार आज परंपरा के नाम पर कुछ दूसरा ही रूप ले चुके हैं। किसी त्योहार पर गहने खरीदने का प्रचलन है तो किसी पर महंगे जानवरों की कुबार्नी देने का। साधारण से रिवाज आज पूरी तरह आर्थिक रंग में रंग चुके हैं।

लोग भी इन्हें मानते रहते हैं बिना यह महसूस किए कि इससे नुकसान उन्हीं का हो रहा है। छोटे शहरों में आज भी पाखंडी बाबाओं और फकीरों का भी जाल फैला हुआ है जिनकी नेमप्लेट अकसर इनके मल्टीटैलेंटेड(?) होने का आभास कराती है। ये अकसर खुद को ट्रैवल एजेंट (विदेश यात्रा करवाने का दावा), फाइनेंशियल एक्सपर्ट(फंसा हुआ धन निकलवाने का दावा), रिलेशनशिप एक्सपर्ट (प्रेम विवाह करवाने का, सौतन से छुटकारा दिलाने का दावा) और मेडिकल एक्सपर्ट (एड्स, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक करने का दावा) आदि बताते हैं। कई लोग इनके झांसे में आ भी जाते हैं और इनका बैंक बैलेंस बढाते हैं। देश में राजसत्ता-तंत्र अपने सामाजिक-आर्थिक दायित्व निभाने में अपेक्षाकृत पीछे ही रहा। दूसरी ओर इन बाबाओं द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य किए जाने लगे। इसके साथ ही भूखों को भोजन से लेकर अन्य सामाजिक कामों में हिस्सेदारी

आजकल विभिन्न सामाजिक वर्गों में अलग-अलग किस्म के अंधविश्वास प्रचलित हैं। इतने जागरूकता अभियानों के बावजूद आज भी आपको गांव-कस्बों में भूत-प्रेत के किस्से सुनने को मिल जाएंगे। वहीं हायर क्लास के अंधविश्वास अलग हैं। इस क्लास में भी असुरक्षा की भावना कम नहीं है। इस वर्ग के लोग यूं तो अत्याधुनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे एयरकंडिशंड आश्रमों वाले गुरुओं के यहां लाखों का चढावा चढाने से लेकर अपनी सफलता/असफलता की वजह लकी चार्म को मानने से भी गुरेज नहीं करते। समाज में अतार्किक विचारधारा वाले इतने अधिक लोग कहां से आ गए? जवाब है, वह परवरिश और माहौल जो हम अपने बच्चों को देते हैं। शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उतने प्रयास नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। संयुक्त परिवारों का टूटना और नई जीवन शैली का एकाकीपन, यांत्रिकता, तनाव आदि से पिछले रसायन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां हर व्यक्ति परेशान और बेचैन हो चला है। इन्हीं सामाजिक-मनोवैज्ञनिक स्थितियों के बीच लोग जाने-अनजाने ऐसे बाबाओं की ओर उन्मुख होने लगते हैं जो लोगों को हर दुःख-तनाव से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं।

की जाने लगी। इस क्रम में उनकी ओर से समानता का भाव स्थापित करने भी का काम किया जाने लगा। धीरे-धीरे वे लोगों के विवाद-झगड़ों का निपटारा भी करने लगे। वे ऐसे काम भी करने लगे जो राज्यसत्ता यानी शासन के हिस्से में आते थे। ऐसे कामों से उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनके कल्याणकारी कामों के तिलिस्म में न केवल गरीब-अभावग्रस्त और कम पढ़ी-लिखी जनता फंसी, बल्कि उनका जादू अपेक्षाकृत संपन्न और शिक्षित लोगों पर भी चला, जो जीवन की विविध जटिलताओं, सामाजिक-मानसिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। इस तरह ये अपने अनुयायी बढ़ाकर सामाजिक वैधता हासिल करते हैं और फिर उसके बल पर राजनीतिक संरक्षण हासिल करने में समर्थ हो जाते हैं। बाबाओं को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए कोई भी राजनीतिक दल पाक-साफ नहीं है। माना जाता है कि राजनीतिक पार्टियां अपना काला धन खपाने-छिपाने के लिए भी बाबा लोगों का इस्तेाल करती हैं। चूंकि बाबाओं के पास अनुयायियों की अच्छी-खासी संख्या होती है इसलिए राजनीतिक दलों के लिए वे वोट बैंक का भी का करते हैं। किसी बात पर आंख मूंदकर विश्वास करने की प्रवृत्ति आज की स्मार्टफोन जेनरेशन से किस कदर तर्कहीन काम करा सकती है। इस वर्ग के लोग आंखें मूंदकर दूसरों का अनुसरण करते है और अपने विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय नहीं ले रहे हैं। वे किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं, क्योंकि वह सालों से होता आ रहा है, या उसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और कभी नहीं सोचते कि उसकी उपयोगिता क्या है। दूसरे शब्दों में कहें, तो ऐसे लोग सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और भावनात्मक अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं। इन लोगों का आइक्यू बेहद कम होता है और इन्हें बेहद आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। ये रैशनली नहीं सोचते, पर इमोशनली बेहद चार्ज्ड होते हैं। इनके दिल में आसानी से किसी चीज के लिए लगाव या नफरत पैदा की जा सकती है और ऐसा होने पर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आंख मूंद कर किया गया विश्वास न सिर्फ इनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित होता है। कबीर की शिक्षाओं का निचोड यही है कि हर तथ्य पर सवाल उठाएं। जब तक खुद उसे परख न लें, तब तक उस पर विश्वास न करें। दार्शनिक प्लूटो ने भी यही कहा है कि शासक हमेशा अनबायस्ड व्यक्ति को ही होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों में भीड का अनुसरण करने की मानसिकता है।

-प्रियंका सौरभ

# धोखाधड़ी गरीबी ने ली स्मृति की जान

**फिल्मी दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है कि यहां चमकते हुए सितारे जब गर्दिश का शिकार होते हैं तो कोई सितारा उसकी जगह देखकर आ जाता है कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्हें आजीवन चमकते रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ परंतु जो लुट गया उसकी याद भी किसी को ना आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। यहां हम उसे चमकते हुए सितारे की याद दिलाना चाहते हैं जिसमें गुरु दत्त देवानंद और किशोर कुमार के साथ काम किया था वह है स्मृति विश्वास।**

स्मृति विश्वास का फिल्म 17 फरवरी 1924 को बांग्लादेश के भरोसापुर शहर में हुआ था। फिल्म इतिहासकार कहते हैं कि शुरू से उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। वह बताओ लीड हीरोइन कामयाब थी और उनके आगे चलकर सह-अभिनेत्री के रूप में भी कामयाब रही परंतु सिर्फ एक गलती के कारण उनके सितारे गर्दिश में आ गए। वैसे तो उन्हें आपने सुपरहिट फिल्म दिल्ली का ठग में देखा होगा। साथ ही हुतात्मा भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीदे आजम मैं भी उन्होंने अभिनय किया था 1956 के अरब का सौदागर फिल्म में उन्होंने हास्य अभिनेता सुंदर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। उनके हमदर्द और मॉडर्न गर्ल फिल्म भी यादगार हैं।

फिल्मों के अलावा उन पर फिल्म गीत मैं भी जवान दिल भी जवान दीवाना दिल का है रुत आए सखी रे जैसे की यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। उनके व्यक्ति का जीवन की बात करें तो यह ज्ञात होगा कि उसे जमाने में डिग्री तक की पढ़ाई की थी। स्कूल के दिनों मे उन्हें बाल कलाकार के रूप में ऑफर्स आए थे जिसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया था। एक दो फेसबुक में काम करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए फिल्मों से दूरियां बनाई और कुछ साल बाद और लीड ऐक्ट्रेस के रूप में पदार्पण किया। अभिनेत्री और गायिका गीता दत्त के साथ उनकी खास दोस्ती हुआ करती थी। गुरु दत्त की बायोग्राफी पुस्तक में स्मृति विश्वास का नाम अनेक स्थलों पर उल्लेखित किया गया है दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि स्मृति विश्वास गुरु दत्त को लेकर गीता दत्त के कान भर करती थी। इस बात का प्रमाण आपको गुरुदत्त की पुस्तक में मिलेगा। स्मृति विश्वास अपने दोस्तों के साथ पार्टी के करने गीता दत्त के घर आती थीं। एक बार तो गुरु दत्त ने अबरार अल्वी को कह दिया था कि उनके यहां आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। खैर, यह बात उसे वक्त की है जब इसमें विश्वास में फिल्म जगत से संन्यास ले लिया था। दरअसल फिल्मकार एचडी नारंग उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे जिन्होंने आगे चलकर उनसे शादी कर ली और फिल्म जगत से संन्यास लेन का निर्णय लिया।

बता दे की एचडी नारंग बहुत बड़े फिल्मकार थे और उनके पास अलग-अलग शहर में प्रॉपर्टी भी थी परंतु 1986 में उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और स्मृति विश्वास और उनके दोनों बेटे राजीव और सत्यजीत के पास सिर्फ एक बांग्ला बच गया था। वह बांग्ला इतना बड़ा था कि एचडी नारंग में उसके दूसरे फ्लोर पर शूटिंग सेट भी बनवाया इतना ही नहीं बाकी एक फ्लोर तालीम के लिए रखा गया। जहां अभिनेत्रियां डांस की प्रैक्टिस करती थी। इस वजह से हेमा मालिनी रेखा रीना राय राजेश खन्ना और सुनील दत्त जैसे सितारे उनके अच्छे दोस्त बन चुके थे। हेमा मालिनी का स्मृति विश्वास के दोनों बच्चों के साथ अक्षर खेला करती थी क्योंकि उनके बंगाल के बगल में ही हेमा मालिनी का भी बंगला था परंतु एक दिन उन्होंने बंगला की मरम्मत करने का फैसला लिया जिस इंसान को कांटेक्ट दिया गया था वह कानूनी तरीके से उसने बांग्ला हड़प लिया और देखते ही देखते ही स्मृति विश्वास अपने दोनों बच्चों को लेकर बेघर हो गई। उस दिन के बाद से आज तक वह 28 बार घर बदल चुकी है अंततः वह अपने बच्चों के साथ नासिक चली गई। जहां वह किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। 3 जुलाई 2024 की रात 9:00 बजे स्मृति विश्वास ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया

**गीता दत्त गुरु दत्त के बीच दरार पैदा करने का आरोप भी उन पर लगा था**

# तीस्ता प्रकरण: अनुरोध और आश्वासनों का सिलसिला

बांग्लादेश और भारत के बीच प्रधानमंत्री स्तर की बैठकों में इसकी चर्चा होती है शीघ्र समापन के आश्वासन के साथ बात आई गई हो जाती है। अनुरोध और आश्वासन का यह सिलसिला समाप्त नहीं हुआ है बजाय इसके घोषणा यह की गई की एक भारतीय तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी ताकि बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा की जा सके। इस पर भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि यह सेल्फ बंटवारे के बारे में एकम बल्कि तीस्ता नदी के भीतर जल प्रवाह के प्रबंधन के बारे में अधिक है। बांग्लादेश के विश्लेषकों का मानना है तीस्ता जल बंटवारे पर चर्चा को हास्य पर छोड़ दिया गया है वह पूछते हैं क्या तीस्ता बंटवारे को जानबूझकर विषय से बाहर किया गया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी व्यापक प्रबंध पुनरोद्धार परियोजना पर चर्चा पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। तीस्ता जलधारा को फिर से बाहर करने की इस मेरा परियोजना को चीन की वित्तीय और तकनीकी सहायता से क्रियान्वित किया जाना है । 2016 से ही चीन और बांग्लादेश इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं चीन के खुद पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस परियोजना में दिलचस्पी लेना भारत की मजबूरी बन चुकी है। सितंबर 2016 में बांग्लादेश जल विकास बोर्ड उतरी बांग्लादेश के ग्रेटर रंगपुर क्षेत्र में तीस्ता को बेहतर ढंग से प्रभावित करने के लिए चीन के पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। बांग्लादेश को तीसरा नदी व्यापक प्रबंध परियोजना के लिए लगभग 987.27 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है। दिखावे के तौर पर बांग्लादेश में विश्व बैंक जापान में दूसरी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग एजेंसियों से बात की है लेकिन बांग्लादेश जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ सचिन कबीर बिन अनवर में जानकारी देते हुए बताइए की इस विशाल परियोजना के फंडिंग के वास्ते हामी भर दी है। तीस्ता बेसिन पर बसा रंगपुर से पंचगढ़ तक का इलाका चीन के टारगेट में है जहां उसे जल प्रबंधन के बहाने डाटा इकट्ठा करने हैं। बांग्लादेश का पंचगढ़ी एक ऐसा सामरिक लोकेशन है जो पूर्वोत्तर के चिकन (सिलीगुड़ी) से मात्रा 67 किलोमीटर की दूरी पर है। कल 315 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी सिक्किम पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र में समाहित हो जाती है। तीस्ता पर

भारत बांग्लादेश के बीच समझौता कब होगा किस देश को कितना पानी मिलेगा फिलहाल यह साफ नहीं है। बांग्लादेश को 48 फीसदी पिस्ता का पानी चाहिए लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की दलील है कि ऐसी स्थिति में उत्तर बंगाल के 6 जिलों में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बंगाल किसके लिए तैयार नहीं तो फिर तीस्ता समझौता कैसे परवान चढ़ेगा। इस सवाल का जवाब देने से दिल्ली भी बच रहा है। शेख हसीना की हालिया दिल्ली यात्रा और उभय पक्षी संगठन से हम चाहे कितना खुश हो जाएं लेकिन तीस्ता कहीं ना कहीं कड़वाहट का कारण बन रहा है। बांग्लादेश के विपक्ष और वहां का मीडिया भूख पड़ा है उनका मानना है कि तीस्ता जल में हिस्सेदारी के बिना समझौते बेकार हैं तीस्ता जल समझौते को अंतिम रूप देने का मामला जनवरी 2011 से आधार में लटका पड़ा है।

अमेरिका के पेंसिलवेनिया स्थित कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय में भू विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर एमडी खाली कुंजमा के एक अध्ययन के अनुसार नदी का क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण नदी का वेग बढ़ जाएगा नतीजा जब बरसात के मौसम में पानी का प्रवाह बढ़ जाता है तो दोनों किनारो पर कटाव की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। नदी के दोनों किनारे पर तटबंधन के कारण तीस्ता की अधिकांश सहायक नदियां और वितरिकाए मुख्य धारा से कट जाएंगी। इससे जल ग्रहण क्षेत्र में गुर्जर स्तर कम हो जाएगा जिसे पीने योग्य पानी और उठा ले ट्यूबवेल के माध्यम से सींची जाने वाले सिंचाई के पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी मालूम नहीं शेख हसीना के सलाहकार इस तथ्य से कितना सरोकार रखते हैं। तीस्ता नदी परियोजना के चक्कर में बांग्लादेश एक नाजुक टूटने से युद्ध में फंस चुका है शेख हसीना की यात्रा जो कुछ होने जा रहा है वह भारत की भूख राजनीतिक एवं सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी उत्पन्न करता है। तीस्ता प्रबंधन परियोजना समझौते पर चीन क्या करेगा इस पर शक्ति निगाहें हैं विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने चीन को तीसरा परियोजना से दूरी रखने की ताकत बांग्लादेश से की है। कुछ साल पहले बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के पास एक बंगाल की खाड़ी में सोना दिया गहरी समुद्र बंदरगाह परियोजना को रद्द कर दिया था जिसे चीन बनाने के लिए उत्सुक था। भारत से लेकर आशाए था विश्लेषण करते हैं कि इस बार भी शेख हसीना सकारात्मक निर्णय पर पहुंचेंगी ।

चिकेन नेक से लगे क्षेत्रों में चीनी कर्मियों की मौजूदगी सचमुच चिंता जनक है तो क्या दिल्ली पर दबाव बनाने के वास्ते से फसाने या खेल खेल रही थीं। जनता सूत्र बताते हैं शेख हसीना 8 से 14 जुलाई के बीच पेइचिंग की यात्रा पर रहेंगी ।

24 जून 2024 को सीपीसी सेंटर कमेटी के नेता लियू चिएनचाव इस सिलसिले में ढाका आए थे उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन लोगों से ढाका पेइचिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ब्रिक्स बांग्लादेश को सदस्य बने का उभय पक्षीय व्यापार घाटे को दुरुस्त करने जैसे विषयों पर वार्ता की लेकिन तीस्ता पर अपडेट को लेकर किसी भी पक्ष में मीडिया से सूचनाओं सजा नहीं कि अब जो दिल्ली में शेख हसीना की यात्रा को बहुत पूर्व उपलब्धि मान रहे थे। इस पर गौर करना चाहिए कि ढाका में क्या चल रहा है।

बांग्लादेश का चेक टाइम क्या क्षमता है कि तीस्ता नदी पर बैराज इंफ्रा जल विद्युत परियोजना नदी के प्रवाह में बढ़ाएं पैदा करने के वास्ते हैं उनको शक है कि भारत तीस्ता के पानी के उचित हिस्से से बांग्लादेश को वंचित करने के उपक्रम में है। लेकिन वह चीज की प्लानिंग पर गौर नहीं करते पावर चीन 30 तक ट्रेनिंग और दोनों तरफ बना कर नदी की चौड़ाई को कम करने का और उसकी गहराई बढ़ाने का प्रस्ताव दे चुका है नदी के दोनों किनारो को काटकर 170 वर्ग किलोमीटर भूमि को पुनः प्राप्त करना उसे भूमि पर आवास और औद्योगिक पार्क बनाना भी इस मेगा परियोजना का लक्ष्य है। वर्तमान में किसका नदी की अधिकतम चौड़ाई 5.1 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 3.1 किलोमीटर है। टीआरसी एमआरपी परियोजना के तहत यह चौड़ाई घटकर 1 किलोमीटर कर दी जाएगी इससे 30 तक नदी के वेग और जल वहां क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

## बाबातिगरी एक मनोवैज्ञानिक खेल

# 'पंडित सोई जो गाल बजावा'

भारतीय दर्शन एवं संत परंपरा में विविध शंकराचार्य, आचार्य गिरी, संत, संन्यासी, तपस्वी, ऋषि, मुनि, यति, नाथ, जोगी, महंत और भी बहुत कुछ है। मठ, मढ़ी, आश्रम, भी है। अखाड़ा परिषद जहां से प्रमाणित साधु कुंभ के उपरान्त निकलते हैं, ऐसी सुनियोजित व्यवस्था है फिर भी कंवल बाबा, चटनी बाबा, के दबार भी हरे-भरे रहते हैं। हाथरस कांड गवाही देते हुए कह रहा हे कि एक सामान्य सिपाही लाखों लोगों का भगवान बन गया। लाखों अनुयायी चरण धूल लेने के लिए व्यग्र होते हैं हुए अपने प्राण भी गंवा देते हैं। ऐसे में दरबार और लाखों अनुयायी पोल खेलते हैं हमारी सामाजिक एवं धर्म व्यवस्था की। आज जब भारत बुलेट ट्रेन, सुपरसोनिक वायुयानों और तकनीकी प्रगति का दावा ठोंक रहा है, उस देश में लाखों लोग किसी के पैरों की धूल लेकर कृतकृत्य हुए जा रहे हैं। चमत्कारी पानी, संतान प्राप्ति की दिव्यऔषधि बना हुआ हे।

भारत जैसे विचारवान देश में इस प्रकार की विवेकहीन धार्मिकता या अंधभक्ति कई बिंदुओं की ओर इशारे कर रही है। जैसे-जैसे भौतिक व्यवस्थाएं संपनन हुई हैं वैसे-वैसे मानसिक जटिलताएं बढ़ती गई हैं। इन जटिलताओं का आसन समाधान पाने के लिए अल्प शिक्षिक या अशिक्षित वर्ग इन फर्जी बाबाओं के दरबार में चक्कर काटता है। अधिकांश भीड़ ग्रामीण महिलाओं की मिलेगी जो अपनी छोटी-छोटी शंकाओं का समाधान इन दरबारों में ढूंढने पहुंच जाती हैं7 ये लोग बहुत छोओे से दायरे का ही जीवन देखते व समझते हैं। ज्यादा बड़ी-बड़ी जटिल पौराणिक बातें, धर्मवेत्ताओं के आख्यान प्रवचन समझने में इन्हें मुश्किल लगती है, चूंकि इनका अधिकांश समय बुद्धि आधारित होता हैं ये बाबा उनके इसी अल्प ज्ञान का लाभ उठाकर आसान शब्दों में लच्छेदार बातें पेश कर देते हैं, उन्हीं के जीवन के उदाहरणों को सुनाकर लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। समस्या ये हे कि भारत जेसे देश में असलीर संत, नकली साधु, कथावाचक, सरस कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर, ओझा, तांत्रिक, सिद्धिवाले बाबा जी गाने वाले बाबा जी, जेल वाले बाबाजी, तेल वाले बाबाजी सबके पास उनकी सधी सधाई श्रोता पार्टी है। सब मामेकम शरणं व्रज

(केवल मेरी शरण में आ जाओ) कहते हुए भक्त पढे जा रहे हैं। लाखों लोग अपना कामधाम छोड़ कर इन बाबाओं का प्रताप बढ़ा रहे हैं। इससे इतना तो स्पष्ट होता है कि ये बाबागिरी एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इस मनोवैज्ञानिक खे का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ प्रभाव राजनीति पर भी है। भारत का आदमी इतना खाली हो चुका हे कि अपने जीवन की समस्या स्वयं न सुलझाकर, कहीं भी उलझने को तैयार हो जाता है।

तुलसीदास ने कहा है- पंडित सोई जो गाल बजावा। ओर ये तरह-तरह के बाबा, तरह के वाचक अपने विचार को इनके माध्यम से विचरधारा बनाने की महत्वाकांखा हासिल कर लेते हैं भारत हैसे देश में सामाजिक जागरूकता की दिशा में बड़े प्रयास चाहिए। धर्म के नाम पर होती सांस्कृतिक होड़, आर्थि क प्रदर्शन की होड़ रोकनी होगी।

प्रस्तुति- प्रियदर्शी दिव्या भारद्वाज

# शहीद लोग वास्तव में अमर हो जाते हैं : मोहन भागवत

**गाजीपुर (जीकेबी)।** आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गाजीपुर के धामूपुर गांव पहुंचे। जहां उन्होने एक कार्यक्रम के तहत परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। मोहन भागवत ने वीर अब्दुल हमीद की जयंती के अवसर पर डा.राम चंद्रन श्रीनिवास द्वारा लिखी गयी किताब ह्लमेरे पापा परमवीरह्व का लोकार्पण किया।

आपको बता दें कि धामूपुर गांव मे वीर अब्दुल हमीद की जयंती पर शहीद अब्दुल हमीद पार्क में पुस्तक के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। पुस्तक के विमोचन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शहीद वास्तव में अमर हो जाते हैं। उनका परिवार अपने आप में एक महान कृति है। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि हमारे देश की परम्परा है कि जीवन जीना उपभोग के लिये नहीं है। जीवन जी कर उसके अनुभव को प्राप्त कर इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान से मिलना है।

मोहन भागवत ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने कच्छ के रण में जो पराक्रम किया, उसके कारण वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गये। मोहन भागवत ने कहा कि शहीदों की स्मृति को सतत जाग्रत रखते हुये हमें स्वार्थ छोड़ कर अपनी जागरुकता को राष्ट्र के निर्माण में लगाना होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास पशुओं के विकास जैसा सिर्फ अपनी चिंता करना नहीं है। मनुष्य का विकास तभी है जब वो दूसरों की चिंता करता है। दूसरों की चिंता करने वाला मनुष्य ही बड़ा कहलाता है। कार्यक्रम के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गाजीपुर के हथियाराम मठ पहुंचे। जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हथियाराम मठ मे दर्शन पूजन किया और मठ के महंत भवानी नंदन यति से भेंट की।

## धर्म छिपाकर मंदिर में विवाह प्रकरण:

# जानकारी होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस

**हाटा, कुशीनगर (जीकेबी)।** पहचान और धर्म छिपाकर युवक ने महिला से शादी रचा ली और बस्ती में किराए के मकान में काफी दिनों तक साथ रहे। कुछ दिन पहले युवक महिला को छोड़कर चला गया। युवक ढूंढ़ती हुई महिला हाटा पहुंची तो सूरज उर्फ अनीस की असलियत उजागर हो गई। महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। गोरखपुर जिले की रहने वाली एक महिला का संपर्क एक साल पहले हाटा कोतवाली क्षेत्र के डुमरी मलाव गांव निवासी सूरज उर्फ अनीस से हुआ। सूरज ने अपना धर्म और पहचान छिपाकर महिला को झांसे में ले लिया और उसके साथ अवैध संबंध बनाया। इसका वीडियो बनाकर युवक महिला के पति के व्हाट्सअप पर भेज दिया। पति ने महिला को छोड़ दिया और सूरज ने मंदिर में महिला से शादी रचा ली और बस्ती में किराए के मकान में दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। सूरज हिंदू रीति-रिवाज से महिला के साथ रहता था। कुछ माह पहले सूरज महिला को छोड़कर चला गया। पता लगाते हुए महिला सूरज के घर डुमरी मलाव पहुंची तो सूरज उर्फ अनीस की हकीकत जानने के बाद वह दंग रह गई।

हाटा कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर सूरज पर ब्लैकमेल कर शादी कर दुष्कर्म करने और बिना मर्जी गर्भपात कराने का आरोप लगाया। पुलिस की जांच में पता चला कि इसके पहले युवक अपने धर्म में दो शादियां करने के बाद तलाक दे चुका है। इंस्पेक्टर राजप्रकाश सिंह ने बताया कि दुष्कर्म और गर्भपात कराने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

# दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्षों की कैद

**पडरौना(जीकेबी)।** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने शुक्रवार को 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दरिंदा विशनुपुरा थाने के कोकिल पट्टी निवासी रवि राय ने दुष्कर्म के बाद मासूम को खेत में छोड़ दिया था। वह गंभीर अवस्था में खून से लथपथ मिली थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने दोषी रवि राय को धारा 307 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पाक्सो एक्ट में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। वादी मुकदमा के अनुसार, 29 अगस्त 2022 की शाम को 7 बजे रवि राय बालिका को कुछ खिलाने के बहाने बुलाया था। 3-4 घंटे बाद भी उसका पता नहीं चला तो घर वाले परेशान हो गए। पूछताछ में जानकारी मिली कि बालिका नहीं है और रवि भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने 112 नंबर डायल करके पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रवि से सख्ती पूर्वक पूछा तो उसने सब कुछ उगल दिया था। उसके बताने के अनुसार बालिका खेत में मिली। उसके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे और खून से लथपथ व गंभीर थी। उसे जिला अस्पताल रविन्द्र नगर पडरौना भर्ती कराया गया और कई दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची थी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादक: पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com